राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

RNI.No. UPHIN/2012/43078

जो लिखेगा, वही टिकेगा

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करे
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | 9511151254 | epaper.swatantraprabhat.com | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, शनिवार, 19 अप्रैल 2025

वर्ष 14, अंक 10, पृष्ट 04,मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

अग्नि शमन प्रभारी ने अपनी टीम के साथ स्वास्थ्य कर्मचारियों को आग बुझाने की दी जानकारी ...03

समस्तीपुर में जमीन विवाद में फायरिंग और पत्थरबाजी, पुलिस ने मौके से 2 खोखा बरामद किया...04

सुप्रीम कोर्ट ने देश में सड़क सुरक्षा बोर्ड के कार्यों पर जताई नाराजगी, कहा- केवल कागजों तक सीमित

स्वतंत्र प्रभात

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बढ़ते सड़क हादसों में घायलों को समय से इलाज और मुआवजा मिलने की घटती संख्या पर नाराजगी जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड केवल कागजों तक सीमित रह गया है। कोर्ट ने कहा कि अब तक इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी नहीं हुई है। सरकार की उदासीनता को लेकर दूसरा मुद्दा यह भी है कि बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी ! यह अब तक स्पष्ट नहीं है। कोर्ट की इस टिप्पणी पर सफाई देते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बोर्ड के इन पदों को भरने के लिए विज्ञापन 2019 में जारी किया गया था। नियुक्तियों को मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना था। लेकिन अब तक कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला।

हिट एंड रन दुर्घटनाओं पर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकारों के रवैये से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसे याचिकाकर्ताओं ने उठाया है। देश में विभिन्न कारणों से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत सहायता नहीं मिलती। ऐसे मामले भी हैं, जहां पीड़ित घायल नहीं होते लेकिन वाहन में फंस जाते हैं। याचिकाकर्ता की मांग है कि ऐसे नोटिफिकेशन जारी किए जाएं जो दुर्घटनाओं की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करें। सरकार के वकील ने कहा कि हस्तक्षेप याचिका में एक मांग यह है कि हिट एंड रन दुर्घटनाओं में जिम्मेदारी तय करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया जाए। यह अत्यंत कठिन है, क्योंकि कई मामलों में यह पता लगाना संभव नहीं होता कि वास्तव में क्या हुआ था।

सरकार के वकील ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश में एक विसंगति है कि मोटर वाहन अधिनियम के मामलों को 10 वर्षों के बाद समाप्त कर दिया जाता है। इससे यह स्थिति उत्पन्न होती है कि अगर कोई व्यक्ति जुर्माना भरता है, तो उसका पैसा चला जाता है, लेकिन अगर वह मामला लंबित रहने देता है तो अंततः मामला समाप्त हो जाता है। यह एक अत्यंत विचित्र स्थिति है। ऐसे मामले जमा होते रहते हैं और फिर कहा जाता है कि बहुत अधिक मामले हैं, जुर्माना केवल 500 या 1000 रुपये है, इसलिए मामले बंद कर दिए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हम उत्तर प्रदेश को इस अंतरिम आवेदन पर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश अधिनियम का प्रभाव यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अपराध किया है और वह जुर्माना नहीं भरता, तो उसका मामला स्वतः समाप्त हो जाता है। इससे एक ऐसी विसंगति उत्पन्न होती है जिसमें अपराधी बिना सजा के छूट जाते हैं।

याचिकाकर्ता के अनुसार, इसके लिए छह अलग-अलग प्रकार के प्रोटोकॉल होने चाहिए। हालांकि, इस कोर्ट के लिए रिट ऑफ मंडेमस जारी करना कठिन होगा, फिर भी हमारा मानना है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल तैयार करने पर कार्य करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया जाता है कि वे त्वरित प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल विकसित करें, ताकि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल सहायता मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 6 महीने का समय दिया है, ताकि वे एक प्रोटोकॉल बना सकें और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवा सकें।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कोर्ट को बताया कि उसने इस पहलू पर कार्य किया है और एक नोट दाखिल किया है, जो हाइवे उपयोगकर्ता सुरक्षा पर आधारित है। इसके बाद कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वे सड़क सुरक्षा पर आधारित यह नोट सभी राज्यों के परिवहन सचिवों को भेजें।

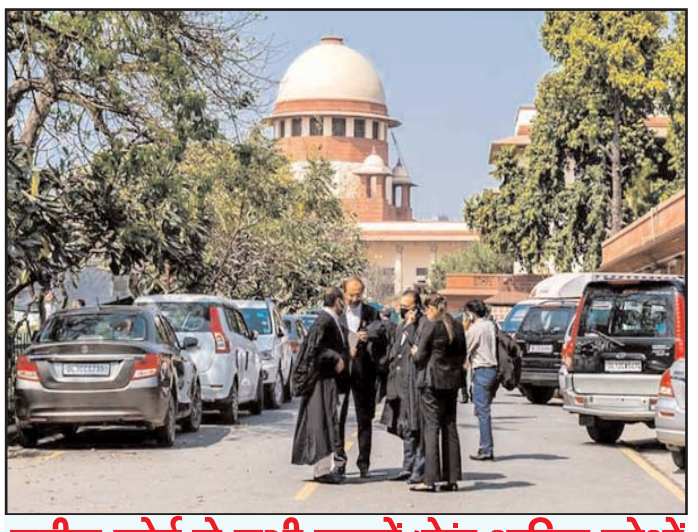

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 6 महीने का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 6 महीने का समय दिया है, ताकि वे एक प्रोटोकॉल बना सकें और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवा सकें। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कोर्ट को बताया कि उसने इस पहलू पर कार्य किया है और एक नोट दाखिल किया है, जो हाइवे उपयोगकर्ता सुरक्षा पर आधारित है। इसके बाद कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वे सड़क सुरक्षा पर आधारित यह नोट सभी राज्यों के परिवहन सचिवों को भेजें। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन पर कार्य करें।

भारतीय शेयर बाजार में तूफानी तेजी, सेंसेक्स 1,508 अंक चढ़कर बंद

शेयर बाजार में चौथे दिन भी दिखी जोरदार तेजी- सेंसेक्स 1508 अंक चढ़कर बंद, निवेशकों ने? 4.5 लाख करोड़ कमाए

स्वतंत्र प्रभात

मुंबई । भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को बड़ी तेजी के साथ बंद हुआ। बाजार में चौतरफा खरीदारी देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1,508 अंक या 1.96 प्रतिशत की तेजी के साथ 78,553 और निफ्टी 414 अंक या 1.77 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,851 पर था।

बाजार में तेजी का नेतृत्व बैंकिंग शेयरों ने किया। निफ्टी बैंक 1,172 अंक या 2.21 प्रतिशत की तेजी के साथ 54,290 पर बंद हुआ। सेंसेक्स पैक में इटरनल, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, सन फार्मा, एसबीआई, बजाज फिनसर्व, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, अदाणी पोर्ट्स, एमएंडएम, टाइटन, एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और एनटीपीसी टॉप गेनर्स थे। केवल मारुति सुजुकी और टेक महिंद्रा ही लाल निशान में बंद हुए । सभी सेक्टरोल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं। ऑटो, फार्मा, एनर्जी, इन्फ्रा, सर्विसेज और निजी बैंक सबसे ज्यादा बढ़ने वाले इंडेक्स थे।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी खरीदारी हुई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 312 अंक या 0.60 प्रतिशत की तेजी के साथ 52,657 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 60 अंक या 0.37 प्रतिशत की बढ़त के साथ 16,410 पर बंद हुआ।

मोतीलाल ओसवाल में टेक्निकल रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट रुचित जैन के अनुसार, यह तेजी महज एक शॉर्ट-टर्म पुलबैक से कहीं अधिक प्रतीत होती है, क्योंकि इसे सभी की व्यापक भागीदारी है, जिसमें खासकर बड़ी कंपनियों के नामों के साथ बैंकिंग और वित्तीय शेयरों से सपोर्ट भी शामिल हैं।

शेयर बाजार में व्यापक स्तर पर तेजी थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर 2,427 शेयर हरे निशान में, 1,522 शेयर लाल निशान में और 157 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए। इस बढ़त के कारण बीएसई का मार्केट कैप बढ़कर 419 लाख करोड़ रुपये हो गया।

कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी। सुबह करीब 9.27 बजे सेंसेक्स 338.13 अंक या 0.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,706.16 पर था, जबकि निफ्टी 120.75 अंक या 0.52 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,316.45 पर था।

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) भारत में फिर से सक्रिय रूप से खासकर घरेलू खपत-आधारित उच्च गुणवत्ता वाले लार्जकैप शेयरों में निवेश कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि मौजूदा वैश्विक संकट में भारत को निवेश का एक स्थिर और भरोसेमंद गंतव्य माना जा रहा है, खासकर तब जब अमेरिका और चीन की संभावनाएं कमजोर दिखाई दे रही हैं। इससे बीएसई के सभी 21 समूहों में लिवाली हुई।

इस दौरान कमोडिटीज 0.56, सीडी 0.95, ऊर्जा 1.13, एफएमसीजी 0.61, वित्तीय सेवाएं 2.00, हेल्थकेयर 0.91, इंडस्ट्रियल्स 0.57, आईटी 0.24, दूरसंचार 2.22, यूटिलिटीज 0.71, ऑटो 1.01, बैंकिंग 2.56, कैपिटल गुड्स 0.75, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.71, धातु 0.25, तेल एवं गैस 0.98, पावर 0.94, रियल्टी 0.49, टेक 1.19, सर्विसेज 1.47 और फोकस्ड आईटी समूह के शेयर 0.21 प्रतिशत उछल गए। वैश्विक स्तर पर मिलाजुला रुख रहा। इससे ब्रिटेन का एफटीएसई 0.59 और जर्मनी का डैक्स 0.24 प्रतिशत गिर गया। वहीं, एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 1.35, हांगकांग का हैंगसेंग 1.61 और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.13 प्रतिशत चढ़ गया।

संक्षिप्त ख़बरें

बिजली कटौती से उपभोक्ता त्रस्त

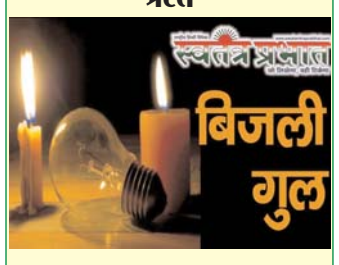

सिद्धार्थनगर। जिले के उसका कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों सामान्य से अधिक बिजली की कटौती हो रही है। बिजली की अधिक कटौती होने से उपभोक्ता त्रस्त है। प्रतिदिन भोर में ही लाइट कट जा रही है। विद्युत उपभोक्ता सतेंद्र पाण्डेय, सुभाष यादव, दिनेश चौरसिया, सचिन चौरसिया आदि लोगो ने बिजली सप्लाई पर्याप्त समय तक करने की मांग किया है।

खराब सड़क- राहगीरों एवं छात्रों को आवागमन में

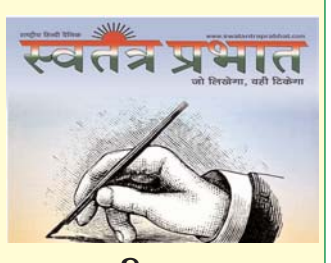

दिक्कत

सिद्धार्थनगर। उसका बाजार कस्बा के संस्कृत महाविद्यालय से किसान इंटर कालेज तक जाने वाली सड़क काफी खराब हो गई है। खराब सड़क से राहगीरों और स्कूली बच्चों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। यह सड़क पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से खराब है। गिट्टियां उखड़ गई है और सड़क में गड्ढे भी बन गए है। बरसात होने पर आवागमन काफी कठिन हो जाता है। क्षेत्र के पवन कुमार, नारायण, कपिल देव, रीना, अमरेश वर्मा, रजनी लोधी आदि ने प्रशासन से सड़क मरम्मत की मांग की है।

मरमत के अभाव में खराब हो रहा है सरकारी भवन

उसका बाजार कस्बा में स्थित ब्लॉक कार्यालय के परिसर में ब्लॉक कर्मियों के लिए बने आवास की दीवारों में बड़े- बड़े पेड़ उग गए है, जिससे भवन खराब हो रहा है। पेड़ की जड़े भवन की दीवार के अंदर जा चुकी है इससे भवन ढह भी सकता है और दुर्घटना भी

लोक निर्माण विभाग- सड़क निर्माण में खराब गुणवत्ता और कोई समय सीमा नहीं

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो।

मथुरा- छाता और मांट तहसील के अंतर्गत सड़क का निर्माण खराब गुणवत्ता और समय सीमा के साथ नहीं हो रहा है सड़क खराब होने की वजह से आए दिन आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है जिससे लोगों की जान जा रही है लोगों ने क्षेत्रीय सड़कों को लेकर शिकायतें भी किए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है पीडब्ल्यूडी विभाग ने सरकार की साख पर बट्टा लगाने की ठान ली है जिससे सरकार की स्वर्णिम योजनाओं पर पलीता लग सके।

पीडब्ल्यूडी ने खराब सड़क बनाई तो क्षेत्रीय विधायक ने सांसद के सामने उठाया मुद्दा

मथुरा- जिले में भ्रमण के दौरान सांसद हेमा मालिनी ने सभी विधायकों के साथ-साथ अधिकारियों की मीटिंग ली मीटिंग के दौरान मांट विधानसभा के विधायक राजेश चौधरी ने बताया चंद दिनों पहले बनी सड़क बाजना से दिल्लू पट्टी और टीटी गांव से खैर रोड तक अभी से उखड़ने लगी है जिसे झाड़ू से इकट्ठा कर सकते हैं ग्रामीण फतुल चौधरी निवासी मुडलिया अर्जुन पट्टी ने बताया मंदिर से गांव तक चार दिन पहले सड़क बनी है अभी से उखड़ने लगी है हमने ठेकेदार से शिकायत की हमारी नहीं सुनी इसी गांव के अध्यापक अर्जुन सिंह ने बताया सड़क निर्माण के दौरान लाइन टू लाइन नहीं मिलाई गिट्टी पर कम तरकूल मिलकर डाल दिया गया निर्माण के दौरान सड़क में बहुत ही डबक हैं गांव बड़ी मुडलिया निवासी मिश्रीलाल ने बताया महीन गिट्टी में तरकूल मिलाकर सीधी सड़क पर डालकर रोड रोलर को घुमा दिया है जिससे सड़क में डबक और अभी से उखड़ने लगी हैं

बिना समय सीमा और खराब सड़क से जा रही है लोगों की जान

मथुरा- अकबरपुर से शेरगढ़ तक रोड निर्माण को शासन ने समय सीमा के साथ मंजूरी दी थी। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते रोड को पूरा नहीं कर पाया। अकबरपुर में नाली ना बनी होने के कारण जल भराव बना रहता है सड़क निर्माण के दौरान 100 मीटर ,200 मी, कहीं-कहीं 400 मी टुकड़े छोड़ दिए गए हैं नौगांव ग्राम पंचायत निवासी सुभाष ने बताया सड़क निर्माण में खराब गुणवत्ता का प्रयोग हुआ है और छोड़े गए टुकड़ों पर निर्माण पूर्ण नहीं होने के कारण विगत 4 महीने में सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की जान चली गई है। लेकिन अभी तक सड़क निर्माण अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा नहीं हुआ है इसी गांव के निवासी मानसिंह ने बताया 2 महीने से काम बंद चल रहा है ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से लिखित में शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है

खराब गुणवत्ता की सड़क

वर्जन- यह पूरा मामला मेरी संज्ञान में नहीं है दिखवाता हूं

सीपी सिंह अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी आगरा

जिला पंचायत अध्यक्ष पति का डिप्टी सीएम,पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष व जिला महामंत्री को अमर्यादित बयान का वीडियो वायरल

स्वतंत्र प्रभात

कौशाम्बी। जनपद के भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर के पति जितेन्द्र सोनकर का एक अमर्यादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, वायरल वीडियो में जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर के पति जितेन्द्र सोनकर एक बन्द कमरें में कुछ लोगों से यह कहते दिख रहे हैं कि लखनऊ में आयोजित अमित शाह की रैली में कौशाम्बी से हम व सांसद विनोद सोनकर ने अपने खर्चे से 50 बसें भेजी थी। जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने न तो किराया दिया और न ही भाड़ा दिया न चाय,पानी पूंछा और न ही लंचबॉक्स पैकेट के लिए भी नहीं पूछा। वायरल वीडियो में जितेन्द्र सोनकर ने कौशाम्बी से भाजपा की पूर्व जिला अध्यक्ष रही अनीता त्रिपाठी व भाजपा के जिला महामंत्री संजय जायसवाल पर पार्टी का रुपया हजम कर जाने का भी आरोप लगाया गया है। जनपद में जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ जिले के भाजपा पार्टी खेमे में हड़कम्प मच गया है। वायरल वीडियो देखने के बाद विपक्षी पार्टियों के लोग आपस में चर्चा करते सुनाई दिये कि जिला पंचायत अध्यक्ष के पति अपनी ही पार्टी का बंटाधार कराने में लगे हुए हैं।हालांकि स्वतंत्र प्रभात समाचार पत्र इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

खैरटिया में पेयजल संकट गहराया, ग्रामीणों ने मंत्री से लगाई गुहार

स्वतंत्र प्रभात

सोनभद्र, ओबरा। ओबरा ब्लॉक के खैरटिया क्षेत्र में व्याप्त भारी पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ÷हर घर नल योजना÷ को खैरटिया में लागू कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कमर कस ली है। इसी क्रम में, खैरटिया के ग्रामीणों ने ओबरा मंडल अध्यक्ष शिवनाथ जायसवाल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री माननीय संजीव कुमार गोंड को एक ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन सौंपने के दौरान ग्राम सेवा समिति के अध्यक्ष शिवदत्त दुबे, अमरजीत कुमार, बहादुर खरवार, धर्मजीत जयसवाल, दुर्गा सिंह गोंड, राजेश जायसवाल समेत कई अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने मंत्री जी को खैरटिया में पेयजल की गंभीर समस्या से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि खैरटिया एक तराई और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां बोरिंग करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में, ÷हर घर नल योजना÷ ही खैरटिया के निवासियों की पानी की समस्या का एकमात्र स्थायी समाधान है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि खैरटिया एक अर्ध-शहरी क्षेत्र है, जिसकी आबादी लगभग 20,000 है और यहां पेयजल की तत्काल आवश्यकता है।ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए, समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने ओबरा मंडल अध्यक्ष शिवनाथ जायसवाल के लेटर पैड पर जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र को तत्काल आवश्यक कदम उठाने के लिए आदेशित किया। मंत्री जी ने जोर दिया कि खैरटिया में पानी की किल्लत एक गंभीर समस्या है और इसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाना चाहिए।खैरटिया के ग्रामीणों को उम्मीद है कि मंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन इस मामले में तेजी से कार्रवाई करेगा और ÷हर घर नल योजना÷ को जल्द ही उनके क्षेत्र में लागू किया जाएगा, जिससे उन्हें पेयजल की समस्या से मुक्ति मिल सकेगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिलाधिकारी महोदय इस आदेश पर कितनी तेजी से संज्ञान लेते हैं और खैरटिया के ग्रामीणों को कब तक राहत मिलती है।

ठगी नौकरी दिलाने के नाम पर 2.5 लाख की ठगी, विरोध करने पर घर में घुसकर हमला

डीएम और एडीएम से 'सेटिंग' का दावा, फिर ढाई लाख की वसूली

स्वतंत्र प्रभात

जौनपुर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी कर्मचारी पर नौकरी दिलाने के नाम पर ढाई लाख रुपये की ठगी और विरोध करने पर पीड़ित के घर में घुसकर जानलेवा हमला करने का सनसनीखेज आरोप लगा है। पीड़ित मोहम्मद जावेद अख्तर ने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत जिलाधिकारी को सौंपते हुए आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की है।

डीएम और एडीएम से "सेटिंग" का दावा, फिर ढाई लाख की वसूली

पीड़ित के अनुसार, तहसील सदर स्थित इलेक्शन ऑफिस के वरिष्ठ लिपिक जगदीश कुमार पटेल ने खुद को उच्च अधिकारियों का करीबी बताकर नौकरी लगवाने का झांसा दिया। "हमारी सेटिंग डीएम और एडीएम साहब से है," - यही कहकर उसने विश्वास जमाया और वाराणसी निवासी एक लड़की को नौकरी दिलाने के नाम पर ?2,50,000 वसूल लिए। इस दौरान कुछ भुगतान ऑनलाइन किया गया,

जिसकी रसीदें व अन्य प्रमाण प्रार्थी ने अपने शिकायती पत्र के साथ संलग्न किए हैं। शेष रकम नकद दी गई थी।

फर्जी लेटर, व्हाट्सएप पर झूठे वादे और सचिवालय का ड्रामा

जब नौकरी को लेकर पीड़ित ने बार-बार पूछताछ की तो आरोपी ने इलेक्शन ऑफिस का फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया और कहा कि जल्द ही नियुक्ति हो जाएगी। पीड़ित की मित्र की बेटी को ऑफिस बुलाया गया, लेकिन जब जॉइनिंग लेटर मांगा गया, तो वह देने में विफल रहा।

इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़ित को लखनऊ सचिवालय तक भेजा और एक कथित अधिकारी ÷दानिश खान÷ से मिलने को कहा। बाद में पता चला कि सभी दस्तावेज और अधिकारी की पहचान पूरी तरह फर्जी थी। पीड़ित को तीन वर्षों से लगातार "आज-कल, परसों" का झांसा देकर मानसिक रूप से भी परेशान किया गया।

पैसे मांगे तो दरवाजे पर पहुंचा आतंक

घटना का सबसे गंभीर पहलू तब सामने आया जब 7 अप्रैल 2025 को शाम 6 बजे पीड़ित ने आरोपी से फोन पर पैसे लौटाने की मांग की। इसके बाद आरोपी ने धमकी देते हुए कहा, "आधे घंटे में अंजाम दिखाता हूं।" ठीक आधे घंटे बाद जगदीश पटेल चार अज्ञात युवकों को लेकर पीड़ित के घर पहुंचा और अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित द्वारा विरोध करने पर सभी हमलावरों ने घर में घुसकर मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग जुटे, तब जाकर पीड़ित की जान बच सकी। जाते-जाते हमलावरों ने चेतावनी दी कि अगर पैसे की मांग दोबारा की तो पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा।

पीड़ित का आरोप- यह सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ होगा

शिकायती पत्र में पीड़ित ने लिखा है कि आरोपी द्वारा किए गए झूठे वादे, फर्जी दस्तावेज और लगातार हो रही धमकियों से प्रतीत होता है कि यह एक सोची-समझी ठगी और साजिश है। संभव है कि इस तरह की धोखाधड़ी और भी कई लोगों के साथ हुई हो, जो डर या शर्म के कारण सामने नहीं आ पाए।

कानूनी कार्रवाई की मांग- पीड़ित ने पूरे प्रकरण की जानकारी के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग, चैट्स और अन्य साक्ष्यों को जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपते हुए आरोपी के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है। इस घटना को लेकर संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की प्रतिक्रिया का इंतजार है।

वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की चुप्पी पर उठे सवाल, मुस्लिम लीग नाराज, बताया 'काला धब्बा'

संसद में हाल ही में पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 ने राजनीतिक हलकों में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की अनुपस्थिति ने इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग (ढ्रूरू) सहित कई विपक्षी दलों को नाराज कर दिया। पार्टी ने इस बारे में तीखी प्रतिक्रिया दी और प्रियंका गांधी की आलोचना की। वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए गए हैं।

प्रियंका गांधी की अनुपस्थिति पर नाराजगी

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संसद में चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी का सत्र में हिस्सा न लेना कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था। समस्त केरल जेम-इय्यथुल उलमा के मुखपत्र 'सुप्रभातम' में प्रकाशित एक संपादकीय में प्रियंका गांधी की अनुपस्थिति को "काला धब्बा" बताया गया। संपादकीय में सवाल उठाया गया कि जब बीजेपी इस विधेयक को आगे बढ़ा रही थी, तब प्रियंका गांधी कहां थीं? साथ ही, यह भी कहा गया कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

राहुल गांधी पर सवाल उठाए गए

प्रियंका गांधी के अलावा, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए गए। संपादकीय में कहा गया कि राहुल गांधी ने वक्फ विधेयक पर अपनी स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की, जबकि वे यह दावा करते हैं कि यह विधेयक देश की एकता को प्रभावित करता है। संपादकीय में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के खिलाफ तीखा रुख अपनाया गया, लेकिन साथ ही इंडिया गठबंधन के तहत संसद में बिल के खिलाफ उनके सामूहिक रुख की सराहना भी की गई।

कांग्रेस सांसद ने विधेयक को बताया असंवैधानिक

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने वक्फ विधेयक को असंवैधानिक और अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि "यह विधेयक संविधान के खिलाफ है और इसे पारित नहीं किया जाना चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष ने एकजुट होकर इस विधेयक का विरोध किया, लेकिन सरकार इसे पारित करने पर अडिग रही। उन्होंने इसे लक्षित कानून भी करार दिया, जिसका उद्देश्य विशेष समुदाय को नुकसान पहुंचाना है।

वक्फ विधेयक 2024 की पारित प्रक्रिया

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद में काफी बहस के बाद पारित किया गया। राज्यसभा में इस विधेयक पर बहस रातभर चली और इसके पारित होने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने इसकी पुष्टि की। इस विधेयक के पक्ष में 128 वोट पड़े जबकि 95 वोट इसके खिलाफ थे, और अनुपस्थित वोटों की संख्या शून्य रही।

वक्फ विधेयक 2025 का उद्देश्य

वक्फ विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन कर भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना है। इस विधेयक के तहत वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता बढ़ाने, पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली में सुधार कर उनकी पारदर्शिता और कार्यकुशलता को बढ़ाना है, ताकि वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन किया जा सके।

विपक्षी दलों का विरोध

इस विधेयक को लेकर विपक्षी दलों ने इसे असंवैधानिक और गलत तरीके से लागू करने का आरोप लगाया है। उनका मानना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन करता है और उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है। विपक्षी दलों ने इसे लक्षित कानून बताया है, जो केवल एक विशेष समुदाय को निशाना बनाता है। वक्फ विधेयक 2024 ने भारतीय राजनीति में हलचल मचाई है, जिसमें कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने इसकी आलोचना की है। हालांकि, सरकार इसे पारित करने पर अडिग रही और इसको एक महत्वपूर्ण कदम बताया। अब यह देखना होगा कि यह विधेयक समाज में किस तरह के प्रभाव डालता है और क्या विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद इसका प्रभावी कार्यान्वयन हो पाता है।

तेजस्वी-राहुल मुलाकात में भी नहीं बनी बात- महागठबंधन में पेंच अभी फंसा हुआ है!

बिहार की राजनीति में 90 के दशक में लालू यादव के ताकतवर होने के साथ ही कांग्रेस समेत अन्य कई राजनीतिक दलों के बुरे दिन शुरू हो गए थे। बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे लालू यादव ने वर्ष 1990 में लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करा कर सबको चौंका दिया था। उस समय आडवाणी को जिस अधिकारी (आरके सिंह) ने गिरफ्तार किया था, उन्हें नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बनाया था। वहीं सरकार को बनाए रखने के लिए लालू यादव ने अनगिनत बार कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों को तोड़ने का काम किया। कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल को तो लालू यादव ने बिहार में अपनी बी टीम बनाकर छोड़ दिया था। लालू यादव सीधे कांग्रेस आलाकमान से डील किया करते थे और बिहार कांग्रेस के नेताओं को हमेशा लालू यादव से डर कर रहना पड़ता था।

बिहार में कांग्रेस नेताओं की हालत इतनी दयनीय हो गई थी कि हाल ही में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के साथ दिल्ली में हुई बैठक में कई नेताओं ने यह शिकायत भी की कि आरजेडी के नेता कांग्रेस नेताओं को सम्मान नहीं देते हैं। बिहार की राजनीति में 90 के दशक में लालू यादव के ताकतवर होने के साथ ही कांग्रेस समेत अन्य कई राजनीतिक दलों के बुरे दिन शुरू हो गए थे। बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे लालू यादव ने वर्ष 1990 में लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करा कर सबको चौंका दिया था। उस समय आडवाणी को जिस अधिकारी (आरके सिंह) ने गिरफ्तार किया था, उन्हें नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बनाया था। वहीं सरकार को बनाए रखने के लिए लालू यादव ने अनगिनत बार कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों को तोड़ने का काम किया। कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल को तो लालू यादव ने बिहार में अपनी बी टीम बनाकर छोड़ दिया था। लालू यादव सीधे कांग्रेस आलाकमान से डील किया करते थे और बिहार कांग्रेस के नेताओं को हमेशा लालू यादव से डर कर रहना पड़ता था।

बिहार में कांग्रेस नेताओं की हालत इतनी दयनीय हो गई थी कि हाल ही में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के साथ दिल्ली में हुई बैठक में कई नेताओं ने यह शिकायत भी की कि आरजेडी के नेता कांग्रेस नेताओं को सम्मान नहीं देते हैं। उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि सम्मान हासिल करना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी के मिशन बिहार से काफी कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है।

बिहार के लगातार दौरे पर जाकर राहुल गांधी ने राज्य की राजनीति को समझने का प्रयास किया। अपने करीबी नेता कृष्णा अल्लावरु को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाकर भेजा। लालू यादव के करीबी माने जाने वाले अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर एक दलित नेता राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लालू यादव और तेजस्वी यादव की नाराजगी के बावजूद कन्हैया कुमार को 'पलायन रोको, नौकरी दो' यात्रा का चेहरा बनकर बिहार की सड़कों पर उतरने का मौका दिया। आने वाले दिनों में लालू यादव और तेजस्वी यादव की नाराजगी के बावजूद पप्पू यादव को भी बड़ी भूमिका देने की खबरें निकल कर सामने आ रही है।

कांग्रेस के आक्रामक तेवरों को देखते हुए लालू यादव काफी हद तक असहज हो गए। उन्होंने अपने बेटे तेजस्वी यादव (जिन्हें वे पहले ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं) को पटना में 17 अप्रैल को होने वाली महागठबंधन की बैठक से पहले ही राहुल गांधी के साथ सब कुछ तय करने के लिए आनन-फानन में दिल्ली भेजा। मंगलवार को तेजस्वी यादव ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर राहुल गांधी के साथ बैठक की। लेकिन राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को कांग्रेस की अहमियत बताने के लिए इसको एक बड़ी बैठक बना दिया। इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के अलावा राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और गुरदीप सिंह सप्पल भी मौजूद रहे। वहीं तेजस्वी यादव अपने साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा और संजय यादव को लेकर गए थे।

लेकिन तेजस्वी यादव की यह दिल्ली यात्रा उनके लिए उतनी लाभदायक नहीं रही, जितनी वह उम्मीद कर रहे थे। कांग्रेस ने आरजेडी के ऑफर (यानी 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने) को सिरे से नकार दिया और पिछली बार की तरह 70 सीटों की मांग रख दी। इतना ही नहीं कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया कि पिछली बार की तरह कांग्रेस कमजोर और हारने वाली सीटों को स्वीकार नहीं करेगी। सीट को लेकर विस्तार से चर्चा पटना की बैठक में होगी। वहीं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर भी कांग्रेस ने फिलहाल अपने पत्ते खोलने से साफ इनकार कर दिया है।

दिल्ली की बैठक बेनतीजा रही, यह बैठक के बाद आए बयानों से भी साफ पता चलता है। बड़ी उम्मीदों के साथ दिल्ली आए तेजस्वी यादव ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि, "पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे के लिए। यह हम लोगों की चीजें हैं। हम लोगों की बातचीत के बाद सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर पत्रकारों ने यही सवाल बैठक से बाहर आए कांग्रेस के नेताओं से भी पूछा। कृष्णा अल्लावरु ने भी साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि , अगर पहली मुलाकात में ही सब कुछ तय हो गया होता तो वे इसकी जानकारी जरूर देते। मतलब साफ है कि गठबंधन में अभी काफी पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस इस बार झुकने को तैयार नहीं है।

बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने है। आरजेडी चाहती थी कि पहले कांग्रेस के साथ सारे मुद्दे तय कर लिए जाएं, फिर गठबंधन में शामिल अन्य राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जाए। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में खरगे के आवास पर हुई पहले दौर की बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। आपको बता दें कि, 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के तहत आरजेडी 144, कांग्रेस 70, सीपीआई (एमएल) 19, सीपीआई 6 और सीपीआई (एम) 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। विपक्षी गठबंधन के प्रदर्शन की बात करें तो, आरजेडी को 75, कांग्रेस को 19, सीपीआई(एमएल) को 12 और सीपीआई एवं सीपीआई(एम) को 2-2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी।

आरजेडी कांग्रेस को 70 में से सिर्फ 19 सीटें जीतने की याद दिलाते हुए, इस बार सिर्फ 50 सीटों पर लड़ने की बात कह रहा है। जबकि कांग्रेस 70 से कम पर मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब सबकी निगाहें, 17 अप्रैल को पटना में होने वाली महागठबंधन की बैठक पर टिक गई है। कांग्रेस सीटों की संख्या और सीटों के नाम के ऐलान के साथ ही उपमुख्यमंत्री के पद पर भी अड़ गई है। आरजेडी जब तक इन मुद्दों पर कांग्रेस की बात नहीं मान लेती है, तब तक कांग्रेस भी मुख्यमंत्री पद को लेकर अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस इस बार एक साझा कार्यक्रम के आधार पर चुनाव में जाना चाहती है।

शैक्षणिक जड़ता की गिरफ्त में हजारीबाग का गौरव- कब मिलेगा विवि को स्थायी कुलपति?

झारखण्ड के हजारीबाग जिले में स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय, जो कभी राज्य की उच्च शिक्षा का एक प्रेरणास्पद और प्रतिष्ठित केंद्र हुआ करता था, आज प्रशासनिक अस्थिरता और असमंजस की स्थिति से जूझ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और गुणवत्ता का प्रतीक रहा यह विश्वविद्यालय पिछले दो वर्षों से अस्थायी कुलपति के नेतृत्व में चल रहा है। शुरुआत में यह व्यवस्था तात्कालिक समाधान के रूप में स्वीकार की गई थी, परन्तु समय के साथ यह एक स्थायी समस्या बन चुकी है। अस्थायी नेतृत्व के पास न तो वह अधिकार होते हैं जो एक स्थायी कुलपति को प्राप्त होते हैं, और न ही वह दीर्घकालिक योजनाओं को कार्यान्वित करने में समर्थ होता है। इसके परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, शोध और प्रशासनिक कार्य ठहराव का शिकार हो गए हैं। आज विश्वविद्यालय की निर्णय प्रक्रिया लगभग ठप पड़ी है। नए पाठ्यक्रमों की स्वीकृति रुकी हुई है, शोध परियोजनाएं अधूरी हैं, और शिक्षकों की नियुक्ति व प्रोन्नति जैसे महत्वपूर्ण कार्य महीनों से लंबित हैं। इससे न केवल अकादमिक वातावरण प्रभावित हुआ है, बल्कि विद्यार्थियों का मनोबल भी गिरा है। वे यह सोचने पर मजबूर हैं कि उनके भविष्य की दिशा किसके हाथ में है। शिक्षकों पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। जब संस्थान का नेतृत्व अस्थिर होता है, तो उनकी व्यावसायिक प्रगति, सेवा शर्तों की समीक्षा और नवाचार की संभावनाएं सभी प्रभावित होती हैं। इससे उनका उत्साह और समर्पण कमजोर पड़ता है, जो अंततः शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अस्थायी कुलपति के पास विश्वविद्यालय के दीर्घकालिक विकास के लिए न तो पर्याप्त समय होता है, न ही संसाधन। इससे संस्थान की बौद्धिक उर्वरता, शोध और नवाचार की संभावनाएं बाधित होती हैं। विश्वविद्यालय एक जीवंत शैक्षणिक केंद्र बनने के बजाय केवल एक प्रशासनिक इकाई बनकर रह जाता है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार और राजभवन को इस पर तत्काल

ध्यान देने की आवश्यकता है। यह केवल विश्वविद्यालय का संकट नहीं है, बल्कि पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था की साख का सवाल है। अब समय आ गया है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय को इस अस्थायी जड़ता से मुक्त किया जाए और इसे एक स्थायी, सक्षम व दूरदृष्टि-संपन्न कुलपति प्रदान किया जाए। यह नियुक्ति केवल एक प्रशासनिक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ऐसी पहल होनी चाहिए जो विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण, शोध कार्यों के सुदृढ़ीकरण और शैक्षणिक माहौल को पुनर्जीवित करने के लिए की जाए। एक प्रभावशाली और दूरदर्शी कुलपति ही इस संस्थान को फिर से उस गौरवशाली स्थिति तक ले जा सकता है, जहां से यह प्रेरणा और उत्कृष्टता का स्रोत बना था। यदि ऐसा शीघ्र नहीं किया गया, तो यह विश्वविद्यालय केवल नाममात्र का संस्थान बनकर रह जाएगा, न कि एक जीवंत और सशक्त शैक्षणिक केंद्र।

हंसराज चौरसिया

संपादकीय

शपथ पत्रों में झूठ का दस्तावेज़ीकरण- कानून की आत्मा पर आघात

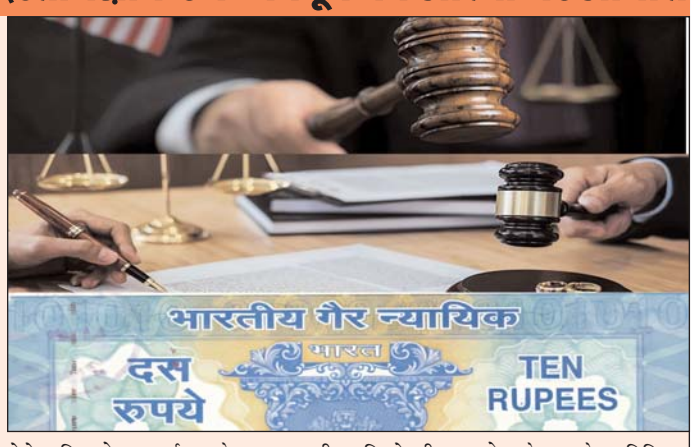

भारतीय न्याय व्यवस्था, जो विश्व की सबसे विशाल और जटिल विधिक संरचनाओं में से एक है, केवल विधानों की व्याख्या का मंच नहीं है, बल्कि यह भारतीय गणराज्य की आत्मा की अभिव्यक्ति है। यह व्यवस्था इस सिद्धांत पर आधारित है कि न्याय की नींव सत्य पर टिकी होनी चाहिए, और इस सत्य को स्थापित करने के लिए जो विधिक औज़ार न्यायालय में प्रयुक्त होते हैं, उनमें सबसे मौलिक और गंभीर औज़ार है शपथ पत्र। शपथ पत्र, मात्र एक लिखित कथन नहीं है। यह एक कानूनी प्रतिज्ञा है एक वचन जिसे कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष यह विश्वास दिलाने के लिए प्रस्तुत करता है कि उसमें उल्लिखित तथ्य संपूर्ण रूप से सत्य, निष्पक्ष और प्रमाणिक हैं। यह प्रतिज्ञा न केवल विधिक दायित्व है, बल्कि नैतिक उत्तरदायित्व का भी प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति अदालत के समक्ष शपथ लेकर कोई तथ्य प्रस्तुत करता है, तो वह स्वयं को उस सत्य के साथ जोड़ता है, जिसे संविधान ने न्याय के लिए अनिवार्य माना है। किन्तु, आज जब हम न्यायालयों में शपथ पत्रों की वास्तविकता पर दृष्टिपात करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि इस मूलभूत प्रक्रिया की पवित्रता में एक गहरा क्षरण हो रहा है। अनेक मामलों में देखा गया है कि पक्षकार जानबूझकर झूठे या भ्रामक शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य केवल अदालत को गुमराह करना, न्याय प्रक्रिया को विलंबित करना, या अपने प्रतिद्वंदी पक्ष को अनुचित रूप से दबाव में लाना होता है। यह प्रवृत्ति न केवल एक व्यक्तिगत दोष है, बल्कि यह संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था को अपवित्र करने वाली विकृति है। शपथ पत्रों का दुरुपयोग अब केवल असाधारण अपवाद नहीं रहा। यह एक सामान्य होती जा रही प्रवृत्ति है, जिससे मुकदमों की अवधि अनावश्यक रूप से लंबी होती है, न्यायालयों पर कार्यभार बढ़ता है और सत्य की खोज में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। इससे न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न उठते हैं। जब आम नागरिक देखता है कि झूठे दस्तावेज़ प्रस्तुत करने वालों के विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तो वह धीरे-धीरे न्यायालयों में अपने विश्वास को खोने लगता है। यह लोकतंत्र के लिए अत्यंत गंभीर संकेत है। वास्तव में, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इस प्रकार के कृत्य के लिए सख्त दंड का प्रावधान है। धारा 191 के अंतर्गत झूठा साक्ष्य देना अपराध है, और धारा 193 के अनुसार ऐसे व्यक्ति को सात वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है। धारा 199 झूठे शपथ पत्र के लिए अलग से दंड निर्धारित करती है। परंतु व्यवहार में इन धाराओं का उपयोग बहुत सीमित होता है। निचली अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक, बहुत कम ऐसे मामले देखे जाते हैं जहाँ शपथ पत्र में झूठे विवरण प्रस्तुत करने पर स्वतः संज्ञान लिया गया हो या कड़ी कार्रवाई की गई हो। इससे यह संकेत जाता है कि इस अपराध को अब भी एक गंभीर अतिक्रमण की बजाय एक प्रक्रियात्मक खामी के रूप में देखा जाता है जो न्याय के सिद्धांतों के साथ अन्याय है। इस स्थिति में सुधार की दिशा में प्रथम प्रयास यह होना चाहिए कि न्यायालय शपथ पत्रों को केवल औपचारिक दस्तावेज़ की तरह न देखकर, उसे न्यायिक विवेक का बुनियादी आधार मानें। न्यायालयों को चाहिए कि वे प्रत्येक शपथ पत्र की प्रामाणिकता पर, विशेषकर जब विरोधी पक्ष संदेह जताए, संजीदगी से विचार करें और आवश्यक हो तो स्वतंत्र जांच के आदेश दें। साथ ही, यदि किसी शपथ पत्र में झूठ या भ्रामक तथ्य प्रमाणित होते हैं, तो उसकी गंभीरता को देखते हुए दंडात्मक कार्यवाही तत्काल की जानी चाहिए। इस विषय में अधिवक्ताओं की भूमिका अत्यंत निर्णायक है। अधिवक्ता न केवल न्यायिक प्रक्रिया के तकनीकी ज्ञाता होते हैं, बल्कि वे न्याय व्यवस्था के नैतिक प्रहरी भी होते हैं। यदि कोई अधिवक्ता अपने मुवक्किल के झूठे शपथ पत्र को जानते हुए प्रस्तुत करता है, तो वह केवल कानूनी कदाचार नहीं करता, बल्कि संपूर्ण न्यायिक प्रणाली की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है। बार कार्उंसिल और न्यायालयों को ऐसे मामलों में स्पष्ट दिशानिर्देश और दंड व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि अधिवक्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी स्पष्ट हो सके। इसके अतिरिक्त, विधायिका को चाहिए कि वह शपथ पत्रों की वैधता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने हेतु तकनीकी उपायों को प्रोत्साहित करे। डिजिटल शपथ प्रणाली, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, और सत्यापन के लिए स्वतंत्र निगरानी तंत्र जैसे नवाचार न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता ला सकते हैं। इससे झूठे शपथ पत्रों की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा और साथ ही तकनीकी रूप से सशक्त न्याय व्यवस्था की नींव तैयार होगी। शपथ पत्र केवल एक कागज़ नहीं, यह एक दृष्टिकोण है। यह उस नागरिक की मानसिकता को प्रतिबिंबित करता है, जो कानून के समक्ष खड़ा है। अगर यह दृष्टिकोण सत्यनिष्ठ, नैतिक और समाजोपयोगी नहीं है, तो फिर उस दस्तावेज़ की कोई विधिक या सामाजिक प्रासंगिकता नहीं रह जाती। और जब ऐसे दस्तावेज़ों की संख्या बढ़ती है, तो संपूर्ण विधिक व्यवस्था केवल प्रक्रिया बनकर रह जाती है न्याय का उद्देश्य गुम हो जाता है।अतः अब समय आ गया है कि हम शपथ पत्र की गरिमा को पुनर्स्थापित करें। इसे केवल दस्तावेज़ नहीं, न्याय की आत्मा मानें। जो व्यक्ति इसे झूठ से कलंकित करे, उसे समाज, विधि और नैतिकता तीनों स्तर पर उत्तरदायी ठहराया जाए। न्यायालय, अधिवक्ता, विधायिका और नागरिक सभी को इस सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करना होगा।न्यायालयों की प्रतिष्ठा, केवल उनके निर्णयों की शक्ति में नहीं होती, बल्कि उस प्रक्रिया की पवित्रता में होती है, जिससे वे निर्णय निकलते हैं। और उस प्रक्रिया की पहली शपथ, वही है कोर्ट में दायर किया गया शपथ पत्र।

हंसराज चौरसिया

बढ़ता ही जा रहा है सत्ता प्रतिष्ठान का दुस्साहस

ये अच्छी खबर है या बुरी ये कहना कठिन है ,लेकिन एक बात साफ़ है कि बैशाखियों पर चलने वाले देश के सत्ता प्रतिष्ठान का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सत्ता प्रतिष्ठान का मकसद येन-केन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी माँ श्रीमती सोनिया गांधी को जेल भेजना है। माँ-बेटे को जेल जाने से अब भगवान भी शायद ही बचा पाए ,क्योंकि अब अदाबत अपने चरम पर है।

नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अब गेंद अदालत के पाले में है। अदालत किसी पर मेहरबान होती है और किसी पर नहीं। हालाँकि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद श्रीमती सोनिया गाँधी और राहुल गांधी की दोबारा गिरफ्तारी आसान नहीं है क्योंकि दोनों पहले से जमानत पर हैं और अब जब तक कि अदालत कोई फैसला नहीं सुना देती तब तक दोबारा गिरफ्तारी नामुमकिन है। मुमकिन है की सत्ता प्रतिष्ठान ने इस मामले में भी कोई कैलेंडर तय कर रखा हो कि कब फैसला आये और कब दोनों को जेल यात्रा पर भेजा जाये ?

पूरे देश को पता है कि ईडी यानि प्रवर्तन निदेशालय इन दिनों सत्ता प्रतिष्ठान के जमूरे की तरह काम कर रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालयने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं के खिलाफ चार्जशीट में ईडी ने आरोपियों पर 988 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है।कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और व्यापारी राबर्ट वाड्रा के खिलाफ गुरुग्राम लैंड डील केस में बुधवार को दूसरी बार पूछताछ हो रही है। पिछले दो दिनों में ये कांग्रेस के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। सत्ता प्रतिष्ठान की इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किये हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका कोई असर सरकार या अदालत पर पड़ने वाला है ,क्योंकि सत्ता प्रतिष्ठान और प्रवर्तन निदेशालय के साथ ही माननीय अदालत का रुख साफ़ है।

मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान ने गांधी परिवार को नेस्तनाबूद करने के लिए पिछले एक दशक में अपने सभी घोड़े खोल लिए हैं किन्तु उसे अभी तक कामयाबी नहीं मिली। विपक्ष के नेता राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता छीनी गयी किन्तु माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे बहाल कर दिया। राहुल से उनका सरकारी बँगला खाली करा लिया गया। राहुल न डरे और न झुके। उल्टे पिछले आम चुनाव में नयी ऊर्जा के साथ अपनी बहन प्रियंका के साथ लोकसभा में वापस लौटे। राहुल ने पिछले दिनों हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव भी हारे किन्तु हिम्मत नहीं हारी और वे कांग्रेस का अधिवेशन करने सत्ताप्रतिष्ठान के नाभि केंद्र गुजरात में जा पहुंचे। सत्ता प्रतिष्ठान को ये सब नागवार गुजर रहा है। परिणाम स्वरूप सत्ता प्रतिष्ठान की और से गांधी परिवार पर आक्रमण और तेज हो गया है।

आने वाले दिनों में कौन जेल जाए और कौन न जाये इससे हमारा कोई ताल्लुक नहींहैं। हमारी चिंता तो सियासत में बढ़ती अदावत को लेकर है। जिनके प्रारब्ध में जेल यात्रा होती है ,वे जेल जाते ही हैं और गांधी परिवार तो सनातन जेल यात्री है लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े नेताओं को जेल यात्रा का कोई ख़ास अनुभव नहीं है। वे आपातकाल को छोड़ कभी जेल नहीं गए। जो दुर्भाग्य से जेल गए वे भी माफियां मांगकर जेल से बाहर आ गये। किसी ने जेल में रहकर अपनी जवानी बर्बाद नहीं की । किसी ने जेल में रहकर न स्वाध्याय किया और न कोई किताब लिखी। बहरहाल मामला राहुल,सोनिया,और रावर्ट वाड्रा का है। इनकी कुंडली में जेल यात्रा का योग होगा तो कोई ताकत रोक नहीं सकती और नहीं तो सत्ता प्रतिष्ठान कितनी भी कोशिश कर ले उसे कामयाबी नहीं मिलने वाली।

देश की राजनीति में वर्ष 2014 के बाद जो तब्दीली आयी है उसमें सबसे प्रमुख बात ये हैकि अपने विरोधियों को किसी न किसी तरह या तो झुका लिया जाये और कोई न झुके तो उसे तोड़ दिया जाये। सत्ता प्रतिष्ठान के आगे झुकने वालों और टूटने वालों की फेहरिश्त बहुत लम्बी है। टीडीपी और जेडीयू जैसे दल तो झुककर सत्ता प्रतिष्ठान की बैशाखी ही बन चुके हैं। बहन मायावती ,भाई अरविंद केजरीवाल हों या नवीन पटनायक तोड़े जा चुके हैं ,लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो सत्ता प्रतिष्ठान से लगातार जूझ रहे हैं, उसे चुनौती दे रहे हैं। गांधी परिवार इस काम में सबसे आगे है। उनके पीछे समाजवादी अखिलेश यादव हैं,राजद के तेजस्वी यादव है। बंगाल की ममता बनर्जी हैं,झारखण्ड के हेमंत सोरेन हैं। दक्षिण के स्टालिन हैं। सत्ता प्रतिष्ठान की तमाम आसमानी-सुल्तानी ताकतें इन तमाम नेताओं को न तोड़ पायी हैं और न झुका पायीं है। बावजूद इसके सत्ता प्रतिष्ठान की कोशिशें जारी हैं ,हरि अनंत ,हरि कथा अनंता की तरह।

कितनी अच्छी बात है कि हमारा देश अमेरिका के टेरिफ वार यानी प्रहार से उतना आक्रान्त नहीं है जितना कि गांधी परिवार से आक्रान्त है । ममता,अखिलेश,तेजस्वी और सोरेन से आतंकित है। क्योंकि ये सब देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने में सबसे बड़ी बाधा है। ये सब मिलकर धर्मनिरपेक्षता का राग अलापते रहते हैं। ऐसे में इन्हें कैसे बर्दास्त किया जा सकता है ? सत्ता प्रतिष्ठान के ओझाओं ने अभी बिच्छुओं को पकड़ने का मन्त्र सीखा है लेकिन हाथ साँपों के बिल में डाल रहे हैं। आप हंस रहे होंगे कि मैं सत्ता प्रतिष्ठान के विरोधियों को बिच्छू और सांप कह रहा हूँ ,लेकिन ये एक कहावत है। मैं न सत्ता प्रतिष्ठान के नेताओं को सांप-बिच्छू कहता हूँ और न किसी दूसरे को ,हालाँकि तमाम ऐसे हैं जो आकंठ जहर से भरे हुए हैं।

अब इस देश की दशा और दिशा देश की अदालतों को तय करना है। वे जो फैसला देंगी उसी से इस देश की भावी राजनीति की दशा और दिशा तय होगी । फिर चाहे मामला वक्फ बोर्ड कि नए कानून का हो या गांधी परिवार के खिलाफ 'मनी लांड्रिंग' का।देश की अदालतें अभी संयोग से पूरी तरह भगवा रंग में नहीं रंगीं है। उनमें आज भी अदालतों में तर्क की ,दलील की ,बहस की गुंजाइश बाक़ी है। ये गुंजाइशें ही एक उम्मीद बांधती हैं ,अन्यथा अब लोकशाही को तानाशाही में तब्दील करने किदिशा में देश बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन हम तो उनमें से हैं जो ये मानते हैं की -को कहि तर्क बढ़ावहि साखा ,होइए वही जो राम रचि रखा।

राम जी ने क्या रच कर रखा है राम जी ही जानें।हम तो इतना जानते हैं कि हमारा सत्ता प्रतिष्ठान परम दुस्साहसी है। वो अपने विरोधियों को नेस्तनाबूद करने कि लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। यानि सत्ता में बने रहने कि लिए हम कुछभी करेगा।

राकेश अचल

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक रवि कुमार अवस्थी द्वारा अनवर ऑफसेट एम्- 58, 59 बेसमेंट विकासदीप बिल्डिंग स्टेशन रोड लखनऊ से मुद्रित ई-4 सेक्टर-एम/29 अपोजिट उष्मान एन्क्लेव अलीगंज लखनऊ 226024 से प्रकाशित **संपादक-राजीव कुमार शुक्ल,** मो0= 7499472288
E-Mail: news@swatantraprabhat.com, RNI No: UPHIN/2019/79073 इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारो के चयन एवं संपादन हेतु पी आर बी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा न्यायलय जनपद लखनऊ ही होगा।

संक्षिप्त खबरें

आज से शुरू हो रही भव्य संगीतमयी श्री राम कथा

पं चन्द्रदेव महराज एवं दधीचि योगी जी के मुखारबिंद से भक्तगण सुनेंगे श्री राम नाम का गुणगान

कादीपुर/सुल्तानपुर-आज दिनांक 18 अप्रैल से राईबीगो कादीपुर में श्री दुर्गा मन्दिर पर भव्य संगीतमयी श्री राम कथा का शुभारंभ किया जा रहा है। इस दौरान राष्ट्रीय कथावाचक पं चन्द्रदेव महाराज अयोध्या तथा योग एवं अध्यात्म गुरु दधीचि योगी जी महराज के मुखारबिंद से भगवान राम के आदर्शों व उपदेशों को श्रद्धालुओं के समक्ष रखा जाएगा। दिनांक 18 अप्रैल से 24 अप्रैल 2025 तक प्रतिदिन शाम 6 बजे से 10 बजे तक श्रद्धालुओं को श्रीराम कथा का गुणगान सुनने का सुनहरा अवसर मिलेगा । श्री राम कथा को धूमधाम से सम्पन्न कराने में समस्त क्षेत्रवासियों का विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। 25 अप्रैल को हवन पूजन एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

समाज में डॉ भीमराव अम्बेडकर के योगदान विषय पर आयोजित की गई गोष्ठी

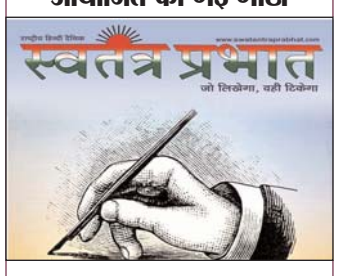

चित्रकूट ब्यूरो: जगदुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय के प्रबंधन विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा डॉ भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर गुरुवार को सामाजिक समरसता में भारत रत्न बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर का योगदान विषय पर एक दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में प्रबंधन विभाग के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने भारत रत्न बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर द्वारा समाज में समरसता, संविधान निर्माण तथा समाज में सभी वर्गों के हितों के लिए किए गए योगदान की जानकारी दी गई। इस दौरान समान नागरिक संहिता, श्रम सुधार कानून, मौलिक अधिकारों सहित अन्य अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को बाबा साहब के आदर्शों को अपने जीवन में उतारते हुए समाज में नए बदलाव के लाने लिए प्रेरित किया। इस मौके पर प्रबंधन विभाग प्रभारी डॉ दलीप कुमार, डॉ भविष्या माथुर, डॉ रवि प्रकाश शुक्ला, विनीत पाण्डेय, वर्षा वर्मा, मोहित तिवारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉ रीना पाण्डेय आदि मौजूद रहे।

फरमाइशी गीत बजाने को लेकर मारपीट, चार गिरफ्तार, एक घायल

पिहानी (हरदोई) बारात में डीजे पर फरमाइशी गाना बजाने को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले। जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। ल पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान कर दिया। पुलिस के मुताबिक बारातियों के डांस में आरोपित शराब के नशे में घुसकर जबरदस्ती डांस कर फरमाइशी गाना लगाने के लिए दबाव बना रहे थे। जानकारी के मुताबिक कोतवाली पिहानी के कुल्लही गांव निवासी अभिवरन पुत्र जगनू की बेटी रिचा का विवाह शिवम पुत्र अमरुतला निवासी उदरा सुरसा के साथ विवाह के लिए बारात बुधवार की रात को आई थी। बारातियों का नाश्ता पानी के बाद द्वारचार के लिए बरात जा रही थी। कुल्लही गांव के ही अरुण, आकाश, सोनू, धीरज बारातियों के डांस में जबरदस्ती घुसकर फरमाइसी गाना लगवा कर डांस करने का दबाव बनाने लगे और घुसकर डांस भी करने लगे। इसी बात को लेकर बरातियों में विवाद हो गया। शराब के नशे में अरुण, आकाश, सोनू, धीरज बारातियों के साथ मारपीट करने लगे। मारपीट में उदरा सुरसा निवासी राहुल घायल हो गए। सूचना पर तत्काल पहुंचे कोतवाल विद्यासागर पाल ने सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से स्थिति पर नियंत्रण किया। बारात में हुई अव्यवस्था को दुरुस्त किया। इस संबंध में कोतवाल विद्यासागर पाल बताते हैं कि शराब के नशे में उक्त चारों ने बारातियों के साथ मारपीट की। शांति भंग में कार्रवाई की गई है।

अखिलेश की काली कलम ने भगवान बुद्ध से लेकर बाबा साहब तक का किया अपमान- प्रभारी मंत्री असीम अरुण

स्वतंत्र प्रभात

हरदोई भारतीय जनता पार्टी का ÷हमारा संविधान हमारा अभिमान÷ अभियान के अंतर्गत 15 से 28 अप्रैल तक चलने वाले कार्यक्रमों में आज नगर के श्रीश चंद्र बारात घर में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. भीम राव अंबेडकर सम्मान संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि जिला प्रभारी मंत्री राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की कलई खोलते हुए बताया कि पिछले छः दशकों के शासन में जो बाबा साहब और उनकी स्मृतियों को सम्मान न दे पाए, वह दल और उसके नेता आज समाज के सम्मान के लिए सड़क से संसद तक झंडा बैनर लिए नजर आ रहे है। संगोष्ठी की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने की, एवं संचालन जिला महामंत्री ओम वर्मा ने किया।

संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथि प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व सांसद प्रियंका रावत, सांसद अशोक रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती एवं जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने अपने विचार साझा किए।

संगोष्ठी में राज्यमंत्री असीम अरुण ने कहा कि बाबा साहब जिस कद के व्यक्तित्व थे, कांग्रेस ने कभी उनको वह सम्मान नहीं दिया। नेहरू गांधी परिवार पिछड़े समाज के व्यक्ति को राजनीति की मुख्य धारा में शामिल होने के खिलाफ था। इसका उदाहरण जब जब बाबा साहब ने राजनीति में अपने कदम बढ़ाए कांग्रेस ने षडयंत्र रच उनको छलने का काम किया। 1937 में बांबे प्रेसीडेंसी का विधान सभा चुनाव हो, या 1952 का लोकसभा चुनाव, नेहरू ने अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल तक में अर्थशास्त्र और कानून के मर्मज्ञ बाबा साहब को जानबुझकर दरकिनार किया। वही समाजवादी पार्टी ने अपने शासन में दलित समाज के चिंतकों के नाम से पहचान वाले जिलों का नाम बदलने का कार्य किया। आज वही दल जब बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई लड़ने की बात करते है तो बात हजम नहीं होती। बाबा साहब और पिछड़े समाज का कोई असली हितैषी है तो वह भाजपा है। जिसने मरणोपरांत बाबा साहब को भारत रत्न से नवाजा। प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहब के सम्मान में पांच तीर्थों को स्थापित किया। पिछड़े दलित समाज को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा।

प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत ने संगोष्ठी में कहा कि पिछड़े और दलित समाज के व्यक्ति को राजनीति से उठकर देखना है कि कौन सा राजनैतिक दल सच में उनका हितैषी है और कौन सिर्फ वोट की राजनीति कर रहा है। भाजपा संघठन 24 घंटे समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए जीजान से लगा हुआ है। भाजपा ने कभी अगड़े पिछड़े और दलित में भेद किया। भाजपा के लिए देश पहले है। कांग्रेस वहीं दल है जिसने संविधान की धज्जियां उड़ा के रख दी। बाबा साहब के संविधान को तोड़ मरोड़ कर 88 बार राष्ट्रपति शासन के जरिए चुनी हुई सरकारों को हटाने का कार्य किया। आपातकाल लगा कर जनता और प्रेस के मौलिक अधिकारों को छीना। अनुसूचित जाति आरक्षण का विरोध, मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध, अल्पसंख्यक संस्थानों में पिछड़े और दलित समाज के हक को लूटना, समान नागरिक संहिता में रोड़े अटकाना का कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया। आज उसी दल के नेता पैजामे के पीछे की पॉकेट में बाबा साहब द्वारा निर्मित देश के ग्रन्थ को लेकर घूमते है और हवा में लहराते हुए पिछड़े समाज की लड़ाई लड़ने का दिखावा करते है। आज की संगोष्ठी का मकसद सिर्फ पिछड़े समाज को जगाना नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को जगाने का प्रयास है। उसे समझना होगा कि देश को बनाने में किसका सबसे बड़ा योगदान है। कांग्रेस पार्टी वंशवाद का शिकार है, पिछड़े समाज का व्यक्ति कभी वहां उच्च पद पर आसीन नहीं हो सकता। भाजपा एकमात्र ऐसा दल है जहां आम कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकता है, बस मेहनत से समाज की सेवा का प्रण उसका संकल्प हो।

सांसद अशोक रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी सर्व समाज के सहयोग से बनी है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका अगला अध्यक्ष किसी परिवार से नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच से निकलता है और वह किसी भी समाज का हो सकता है। इसलिए भाजपा को सभी समाज का विश्वास हासिल हुआ है। तीन बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनना जनता के आशीर्वाद से संभव हुआ। जिसमें पिछड़े और दलित समाज का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पिछड़े और दलित समाज को सिर्फ वोट बैंक तक सीमित रखा। कभी उसे मुख्यधारा में शामिल करने के लिए किसी योजना पर कार्य नहीं किया। आज वहीं दल अपनी खत्म होती राजनैतिक जमीन को बचाने के लिए झूठे प्रपंच कर रहे है। पिछड़े और दलित समाज में खाई खोदने का कार्य कर रहे है, लेकिन उनके मंसूबों पर हमेशा पानी ही फिरा है क्योंकि जनता को मोदी और योगी के नेतृत्व पर विश्वास है।

जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पर बढ़ते हुए देश को एकसूत्र में बांधकर विकसित भारत यात्रा की ओर अग्रसित है। भाजपा की कल्याणकारी योजनाओं में सभी धर्म और जाति के लाभार्थियों को लाभ दिलाने का कार्य किया गया। पीएम मोदी के शासन काल में 8 संविधान संशोधन हुए, जो परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को नहीं बल्कि राष्ट्र की एकता को समर्पित रहे। पीएम मोदी ने बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान की 75वीं वर्षगांठ को ऐतिहासिक रूप में मनाने का कार्य किया। देश के सभी नागरिकों को इस अभियान के से जुड़कर अपने संविधान निर्माता के विषय में जानने और उनके सम्मान में समाज में फैली भ्रांतियों को मिटाने का मौका दिया है। हमें इसका लाभ लेकर अपनी युवा पीढ़ी को सच का सामना करना है। संगोष्ठी में बौद्ध भिक्षु भंते एवं जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमवती ने विचार साझा किए और कार्यक्रम का समापन अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष महिपाल गौतम के भाषण से संपन्न हुआ। संगोष्ठी में उपस्थित रहे नगर पालिका अध्यक्ष सुखसागर मिश्रा, जिला महामंत्री अनुराग मिश्र, सतेंद्र राजपूत, जिला मंत्री अविनाश पांडे, नीतू चंद्रा, मीना वर्मा, आज़ाद भदौरिया, जिला मीडिया प्रभारी गांगेश पाठक सह मीडिया प्रभारी परेश गुप्ता, सत्यम शुक्ल, महिला मोर्चा अध्यक्ष अलका गुप्ता, नगर अध्यक्ष मुदित बाजपेई, निवर्तमान नगर अध्यक्ष अजीत उपाध्याय, मीनाकुमारी, निधि सिंह, अनुराधा मिश्र, सुहाना जैन, शोभना सिंह, सोशल मीडिया प्रभारी प्रद्युम्न आनंद, अनुराग श्रीवास्तव आदि।

मायावती ने सपा पर लगाया दलित वोटों के लिए तनाव और हिंसा भड़काने का आरोप

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर दलित वोटों के लिए तनाव और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने सपा की बयानबाजी और कार्यक्रमों को संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करार दिया। मायावती ने दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों से सपा के बहकावे में न आने की अपील की है। बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा, "विदित है कि अन्य पार्टियों की तरह आए दिन सपा द्वारा भी पार्टी के खासकर दलित लोगों को आगे करके तनाव व हिंसा का माहौल पैदा करने वाले इनके अति विवादित बयानबाजी, आरोप-प्रत्यारोप व कार्यक्रम आदि का जो दौर चल रहा है।

अग्नि शमन प्रभारी ने अपनी टीम के साथ स्वास्थ्य कर्मचारियों को आग बुझाने की दी जानकारी

स्वतंत्र प्रभात

मिश्रिख (सीतापुर) अग्नि शमन प्रभारी मिश्रिख राजबहादुर दुबे ने अपनी टीम के साथ आज महर्षि दधीचि सामुदायिक स्वास्थ्य मिश्रित में माक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन करके सभी कर्मचारियों को आग बुझाने के तरीके और सुरक्षा उपायों के बारे में विस्त्रत जानकारी देकर जागरूक किया। तथा सभी लोगों को जागरूक करने की अपील की । इस मौके पर अग्निशमन प्रभारी ने बताया है। कि गैस सिलेंडर आदि उपकरणों में अचानक आग लगने पर घबराने की कतई जरूरत नही है। उसे बहुत ही आसानी से बुझा कर आग पर काबू पाया जा सकता है। अगर अचानक आग लग जाती है। तो नजदीकी अग्नि शमन स्टेशन में फोन करके सूचना दे। अग्नि शमन टीम तत्काल मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पा लेगी। आयोजित मांक ड्रिल में अग्नि शमन प्रभारी ने गैस सिलेंडर में आग लगाकर उसे बुझाकर सभी को दिखाया । तथा प्रत्येक मांह सुरक्षा उपकरणों की जांच कराने की हिदायत दी। उन्होने बताया कि अग्नि शमन सुरक्षा सेवा सप्ताह के तहत यह आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूली बच्चों, सामाजिक संस्थाओं के साथ ही सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को बराबर जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर अग्नि शमन टीम में शामिल समीउल्ला, विकास वर्मा तथा महर्षि दधीचि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्वास्थ्य अधीक्षक डा. प्रखर श्रीवास्तव, रवी विश्वकर्मा सहित चिकित्सालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।

84 वां निशुल्क नेत्र शिविर आयोजित हुआ

स्वतंत्र प्रभात

सण्डीला (हरदोई) सीतापुर आई हॉस्पिटल, सीतापुर एवं लाला गंगाप्रसाद मानव कल्याण, सण्डीला के संयुक्त तत्वावधान में 84वाँ निःशुल्क नेत्र परीक्षण व निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु नेत्रशिविर का आयोजन, नगर कल्याण समिति (नियर आइडियल स्कूल), सण्डीला में आयोजित किया गया। इस शिविर का उद्घाटन विकास खण्ड कछौना के अपर कार्यक्रम अधिकारी अतुल कुमार राय ने किया। शिविर प्रारम्भ होने से पूर्व विश्व के कल्याण के लिए, संयोजक डॉक्टर सत्यप्रकाश गुप्ता के संयोजन में हवन किया गया व साथ ही टीबी रोग से ग्रसित 5 मरीजों को निःशुल्क खाद्य किट भी संस्था के द्वारा प्रदान की गई।दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ करते हुए एपीओ अतुल कुमार राय ने कहा कि डॉक्टर सत्यप्रकाश व उनकी संस्था के सहयोगीगण द्वारा यह एक बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है। ये सब लोग इस निःशुल्क शिविर का प्रत्येक महीने आयोजन कर रहे हैं और हजारों गरीबों की आँखों के निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन करवा चुके हैं। आज के मतलब के समय में यह संस्था वास्तव में बहुत नेक कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नर सेवा ही वास्तव में नारायण सेवा है।बताते चलें कि यह निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर पिछले सात वर्ष से संयोजक डॉक्टर सत्यप्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में हजारों बेसहारा, गरीब आशक्तजनों की आँखें, संस्था के द्वारा निःशुल्क सही कराई जा चुकी हैं।संस्था में सण्डीला नगर व आसपास के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति जुड़ें हैं। इनमें पूर्व शिक्षक व वरिष्ठ भाजपा नेता विशुनदयाल शुक्ला, संतकृपाल नगर के सामने स्थित सीएनजी व पेट्रोल पंप के मालिक शिवनारायण गुप्ता, पूर्व प्रधानाचार्य भगवान बुद्ध इण्टर कॉलेज, सण्डीला अरविंद अस्थाना, हरदोई की निःस्वार्थ समाजसेवी विभा गुप्ता, एडवोकेट श्रीकांत गुप्ता, अपर कार्यक्रम अधिकारी, बेहन्दर/कोथावाँ व नगर के निःस्वार्थ समाजसेवी आलोक कुमार अस्थाना, समाजसेवी नितिन शर्मा, राकेश मोहन, शिवाजी, राधेश्याम आदि निःस्वार्थ लोग डॉक्टर सत्यप्रकाश गुप्ता के मार्गदर्शन में प्रत्येक महीने के तीसरे बुद्धवार को इस नेक कार्य में सहयोग करते हैं।इस अवसर पर उपरोक्त सदस्यों के अतिरिक्त सीतापुर आई हॉस्पिटल से आई नेत्र चिकित्सक डॉक्टर श्रुति, रामगोपाल शुक्ल, शहनवाज हुसैन, अनवर हुसैन, नर्स हमजा, नर्स समीक्षा आदि टीम में सम्लित रहे।

डॉ नन्द किशोर को दी गयी भावभीनी विदाई

स्वतंत्र प्रभात

हरदोई विगत दिवस देर शाम बसंत लीला होटल में संयुक्त निदेशक कृषि डॉ नन्द किशोर को भावभीनी विदाई दी। जनपद हरदोई में उपनिदेशक कृषि के रुप में कार्यरत रहे डॉ नन्द किशोर अब अलीगढ़ मण्डल में संयुक्त निदेशक कृषि के रुप में अपनी सेवाएं देंगे। विदाई कार्यक्रम में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने संयुक्त निदेशक को पुष्प गुच्छ भेंट किया। उन्होंने डॉ नन्द किशोर को शाल उढ़ाई व राम दरबार की प्रतिमा भेंट की। मुख्य विकास अधिकारी ने डॉ नन्द किशोर को भगवान कृष्ण की प्रतिमा भेंट की। जिलाधिकारी ने भावुक होकर अपने उदगार व्यक्त करते हुए कहा कि संयुक्त निदेशक कृषि कभी भी निराश न होने वाले अधिकारी रहे। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा व तन्मयता के साथ निर्वहन किया। जिलाधिकारी ने उदाहरणों के माध्यम से डॉ नन्दकिशोर के बेदाग कार्यकाल पर प्रकाश डाला। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरूरानी ने कहा कि उपनिदेशक कृषि के रुप में डॉ नन्द किशोर सभी विभागों को साथ लेकर चलने की क्षमता रखते थे। अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह ने कहा कि उपनिदेशक कृषि का पूरा कार्यकाल बेदाग रहा। अन्य अधिकारियों ने भी उपनिदेशक कृषि के साथ अपने यादगार लम्हों को रखा। अंतिम वक्ता के रुप में अपनी बात रखते हुए संयुक्त निदेशक कृषि ने कहा कि जब उन्होंने कृषि विभाग में सेवा शुरू की थी उस समय उनके जिलाधिकारी जी के मित्तल जी थे जो एक बेहतरीन जिलाधिकारी थे और

कार्यकाल के अंतिम पड़ाव पर पर मंगला प्रसाद सिंह के रुप में ऐसे जिलाधिकारी मिले जिन्हे मानवीय संवेदना और प्रशासकीय क्षमता के मामले में उनके समकक्ष रखा जा सकता है। उन्होंने जिलाधिकारी को उन पर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद दिया। बच्चों की प्रतिभा निखारने में शिक्षक व अभिभावक की भूमिका अहम- सुनील कुमार

सोनभद्र ओबरा-चोपन मार्ग पर कमला पेट्रोल टंकी बनी नियमों का अड्डा, स्कूली बच्चों की सुरक्षा खतरे में

स्वतंत्र प्रभात

सोनभद्र। ओबरा-चोपन मार्ग पर स्थित कमला पेट्रोल टंकी इन दिनों खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाने का केंद्र बन गई है। यहां प्रतिदिन ओवरलोड और बिना नंबर प्लेट वाली बालू से लदी ट्रकों का जमावड़ा देखा जा सकता है। रोड के किनारे पत्थर, बस्सी गिल बालू गिरे और बिखरे पड़े हुए हैं, जिससे आम राहगीरों को भारी असुविधा और खतरे का सामना करना पड़ रहा है।चिंताजनक बात यह है कि इस पेट्रोल टंकी के ठीक बगल में मां शारदा पब्लिक स्कूल एवं देवी पब्लिक स्कूल स्थित हैं, जहां लगभग सैकड़ों बच्चों का प्रतिदिन इसी रास्ते से आना-जाना लगा रहता है। दो स्कूलों के बीच में पेट्रोल टंकी पर गाड़ियों का जमावड़ा बच्चों का ध्यान भी आकर्षित करता है, जिससे उनकी सुरक्षा और भी अधिक खतरे में पड़ गई है।

प्रत्येक दिन इस पेट्रोल पंप पर ओवरलोड बालू की गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जिनसे लगातार पानी टपकता रहता है, जिससे सड़क पर फिसलन का खतरा बना रहता है। नगर से निकलने वाले बरसात के पानी का नाला भी टूट गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पेट्रोल टंकी पर खुलेआम कुर्सी लगाकर दबंग घात लगाए बैठे रहते हैं। ये इतने दबंग हैं कि पत्रकारों द्वारा सच्चाई उजागर करने की कोशिश करने पर उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी तक देते हैं। सबसे गंभीर चिंता का विषय यह है कि यदि पत्रकार सच्चाई लिखते हैं तो उन्हें फर्जी मुकदमा करने की धमकी दी जाती है।इनमें से ज्यादातर ट्रकों पर नंबर प्लेट मौजूद नहीं है। ट्रक मालिक निर्भीक होकर सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, और राजस्व को क्षति पहुंचा रहे हैं, जिसकी कीमत स्थानीय जनता को चुकानी पड़ रही है। आस-पास के क्षेत्रीय निवासियों का कहना है कि बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के कारण यदि कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट जाती है, तो पीड़ितों के लिए न्याय की उम्मीद धूमिल हो जाती है। बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां सड़क पर तेज गति से चलती हैं, जिसके कारण आस-पास के लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। इसके अतिरिक्त, ये भारी वाहन सड़कों पर तेज गति से दौड़ते हैं, जिससे कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है। शारदा मंदिर से गजराज नगर और डिग्री कॉलेज, बिल्ली स्टेशन तक इसी तरह का खतरा बना रहता है।इस गंभीर समस्या के साथ-साथ, शारदा मंदिर चौराहे पर स्थापित पुलिस केंद्र की निष्क्रियता भी चिंता का विषय बनी हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार, जब से यह पुलिस केंद्र बना है, तब से इस पर ताला लटका हुआ है।

पुलिस केंद्र में ताला लगे रहने के कारण असामाजिक तत्वों और मनमानी करने वाले वाहन चालकों का मनोबल बढ़ गया है, जिससे क्षेत्र में अराजकता का माहौल है और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ गई है।जब पत्रकार बंधुओं ने इस संबंध में कमला पेट्रोल टंकी के कर्मचारियों से पूछताछ करने का प्रयास किया, तो पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने हमेशा की तरह यही रटा-रटाया जवाब दिया कि ये गाड़ियां केवल तेल भरवाने के लिए यहां रुकती हैं। हालांकि, पानी से लबालब और बिना नंबर प्लेट की इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों की लगातार उपस्थिति कई गंभीर सवाल खड़े करती है, जिनकी जांच आवश्यक है।यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इस क्षेत्र में परिवहन नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है और संबंधित अधिकारी इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं।

ट्रक मालिक की दबंगई और पत्रकारों को धमकाना स्थिति की गंभीरता को और बढ़ाता है, खासकर दो-दो स्कूलों के लगभग सैकड़ों बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। आम जनता की सुरक्षा और सुविधा को दांव पर लगाकर किए जा रहे ऐसे गैरकानूनी कृत्यों पर प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। शारदा मंदिर चौराहे पर पुलिस केंद्र की निष्क्रियता भी प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है, जिसे तुरंत दूर किया जाना चाहिए ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनी रहे और पत्रकारों को निर्भीक होकर अपना काम करने का सुरक्षित माहौल मिल सके, साथ ही स्कूल के बच्चों की सुरक्षा भी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित की जा सके।

प्राथमिक विद्यालय तड़ौरा में शारदा संगोष्ठी व वार्षिकोत्सव का हुआ आयोजन

स्वतंत्र प्रभात

सांडी विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय तड़ौरा में गुरुवार को शारदा संगोष्ठी एवं वार्षिकोस्त्व कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी डॉ. सुनील कुमार ने दीप प्रज्जवलन व मां शारदा के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि श्री कुमार ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं, शिक्षक और अभिभावक मिलकर इनको निखारने का काम करें।शिक्षक अजीत शुक्ल ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जितनी भूमिका शिक्षक की है उतनी ही उनके माता-पिता की भी है। दोनों का समवेत प्रयास बच्चों की प्रगति में सहायक होगा।वार्षिकोत्सव में वार्षिक परीक्षा में प्रथम ,द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कक्षा एक में नवीन नामांकन करने वाले बच्चों को भी पुस्तक देकर पढाई के प्रति प्रेरित किया गया।

पांचवी कक्षा उत्तीर्ण कर चुके बच्चों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले शिवांशु दुबे, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले आयुष दुबे व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा चांदनी को खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं विद्यालय में बेहतर कार्य करने के लिए शिक्षा मित्र विनोद कुमार व अर्जुन सिंह को विद्यालय के उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान संतोष यादव, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव,शिक्षक विजय वर्मा, अभिभावक राम मुरारी, नरेश कुमार, राजीव कुमार, मंजू यादव, उर्मिला देवी, अनीता देवी व जितेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे।

पूर्व सपा विधायक ने निशुल्क मोक्ष रथ जनता को किया समर्पित

● बाबा जनवारी नाथ धाम में विधिवत पूजन अर्चन के बाद शुभारंभ

स्वतंत्र प्रभात

लंभुआ। सुल्तानपुर समाज सेवा का कोई अलग रूप नहीं होता है, समाज सेवा किसी राजनीति से प्रेरित नहीं होती, यह कभी भी कहीं भी की जा सकती है। ईमानदारी से की गई जन सेवा ही सच्चा धर्मार्थ है। उक्त विचार बाबा जनवारीनाथ धाम में। विशुल्क मोक्ष रथ जनता को समर्पित करने के मौके पर पूर्व सपा विधायक संतोष पांडे ने व्यक्त किए। लंभुआ विधानसभा सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने गुरुवार को बाबा जनवारीनाथ धाम से मौनी महाराज की उपस्थिति में विधिवत पूजन अर्चन के बाद निशुल्क मोक्ष रथ का शुभारंभ किया। इसके लिए बाकायदा उन्होंने अपनी तरफ से समाज को एक बस प्रदान की। पूर्व विधायक श्री पांडे ने कहा कि यह सेवा समाज के सभी जाति धर्म के लोगों के लिए है। कभी-कभी जब मैं दाह संस्कार के समय घाट पर जाता था, तो देखता था कि समाज के गरीब कमजोर लोग ऐसी व्यवस्था करने में अपने को काफी असहज महसूस करते थे और वह लोग चाहते भी थे कि अंतिम यात्रा में समाज के अन्य लोग भी आए। लेकिन व्यवस्था करने में असमर्थ होते थे। बस मेरे मन में विचार आया कि मैं समाज के लिए ऐसी व्यवस्था दूं। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था लावारिस लाशों के लिए भी रहेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी आरव ग्लोबल संस्था के नितिन तिवारी भी ऐसे सामाजिक कार्य में साथ दे रहे हैं। मौनी महाराज ने कहा कि निशुल्क मोक्ष रथ सर्व समाज का है, यह किसी सत्ता या किसी राजनीतिक दल का नहीं है। आज एक वाहन आया है कल सैकड़ो वाहन शामिल होंगे। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई गणमान्य को पूर्व विधायक ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मौके पर वरिष्ठ सपा नेता राजबली यादव, विधानसभा अध्यक्ष सतपाल यादव, परमात्मा यादव, अतेंद्र जायसवाल, मुलायम यादव, अजीत श्रीवास्तव, बंसराज यादव, हरिकेश यादव, हरीश यादव, यगदेव भट्ट समेत सैकड़ो लोग मौजूद थे।

संक्षिप्त खबरें

अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की मांग को लेकर महिला शिक्षिकाओं ने बीएसए कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा

सिद्धार्थनगर। अंतर्जनपदीय स्थानांतरण को लेकर उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष सुषमा सिंह की अगुवाई में शिक्षिकाओं ने बृहस्पतिवार को बीएसए कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। बेसिक शिक्षा सचिव को संबोधित ज्ञापन में लिखा है कि आकांक्षी जिला घोषित होने के बाद हुए तीन अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के उपरांत भी वर्ष 2023 में सिर्फ दस प्रतिशत शिक्षिकाओं को इसका लाभ मिला। इसके बाद शिक्षिकाओं को अपने गृह या इच्छित जनपद में स्थानांतरण नही हो सका है, इससे इनकी घर गृहस्थी बिगड़ रही है। मांग किया कि स्थानांतरण के लिए एक स्थाई नीति बनाई जाए एवं अन्य विभागों के तरह ही एक निर्धारित अवधि तक एक जनपद में सेवा करने के उपरांत मनचाहा स्थानांतरण कर दिया जाए। निर्धारित दोषपूर्ण भारांक सुधार किया जाए, असाध्य रोगियों का मेडिकल टीम गठित कर भौतिक परीक्षण किया जाए न कि सिर्फ डॉक्टर की रिपोर्ट पर ही असाध्य रोगी मान स्थानांतरण प्रक्रिया में इसका लाभ दिया जाए। मागों से संबंधित ज्ञापन वित्त एवं लेखाधिकारी नीलोत्तम चौबे को सौंपा। इस दौरान महामंत्री रश्मि जायसवाल, निशात अंजुम,शशिकला सिंह, आरती शुक्ला, सीमा द्विवेदी, संचिता मजूमदार, रूपा, निधि, ऋचा, साधना, शीला यादव, शाइस्ता, उपमा, बीनू शर्मा, मधुरानी, वंदना, कविता, शिखा आदि मौजूद रहीं।

ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत

सिद्धार्थनगर। ढेबरुआ थाना क्षेत्र के परसा - महादेव स्टेशन के बीच बुधवार की रात रेड़वरिया के पास ट्रेन की चपेट में आने से लगभग पचास वर्षीय अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची ढेबरुआ थाना पुलिस शव की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। पुलिस शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

वारंटी गिरफ्तार

सिद्धार्थनगर। जिले की मोहाना थाना पुलिस ने एक नफर वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दुष्कर्म सहित पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त रितिक उर्फ अंशू जयसवाल पुत्र राजेश जयसवाल निवासी बर्डपुर तिराहा, थाना मोहाना, जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शुद्धोधन चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक पप्पू कुमार गुप्ता, हेड कांस्टेबल रामाज्ञा पासवान, कांस्टेबल सूरज यादव शामिल रहे।

तानाशाह सरकार का तानाशाह पुलिस प्रशासन

गरीबों पर जुल्म अत्याचार अन्याय अब बर्दाश्त नहीं करेंगे

हरदोई में गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है वाहन चेकिंग के नाम पर चारों तरफ लूट मची है। क्या सभी नियम और कानून गरीबों के लिए ही बने हैं? ई-रिक्शा चालकों के पास पूरे कागज होने के बावजूद भी उनके ई-रिक्शा जबरदस्ती चीज कर दिये जाते हैं। जो रिक्शा वाला ट्रैफिक पुलिस वालों को पैसे दे देता है उसकी गाड़ी सीज नहीं की जाती है रिक्शा वाला चाहे जेवर बेचकर या कोई सामान गिरवी रखकर पैसे ले आए लेकिन पुलिस वालों को पैसे चाहिए।

गरीब परेशान है जिसका रिक्शा सीज हो जाता है 15 से 20 दिन लगते हैं कोर्ट से छुड़वाने में 10 से 15000 रुपए खर्च भी आता है और 15 /20 दिन पुलिस लाइन में रिक्शा खड़ा रहता है इन गरीबों के घर का 15 /20 दिन घर का चूल्हा कैसे जलता होगा और घर का खर्चा कैसे चलता होगा यह इन घूसखोर पुलिस वालों को नहीं मालूम है। जिस गरीब का रिक्शा 15 से 20 दिन रिक्शा खड़ा रहेगा और 10 से 15000 रुपए देना भी पड़ेगा उसका घर का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा किस्त भी देनी होती है और खर्च भी होते हैं। अगर अब किसी का रिक्शा पकड़ा जाता है पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है हमारे पास फोन करिए मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा आपको न्याय दिलाऊंगा किसी गरीब के साथ अत्याचार अन्याय नहीं होने दूंगा।

समस्तीपुर पहुंचे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, बोले- 'जमीन सर्वे से जमीनी विवाद में कमी आएगी'

स्वतंत्र प्रभात

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी गुरुवार को समस्तीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में भूमि विवाद काफी है, इसके लिए विशेष भूमि सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इसके पूरा होने पर भूमि विवाद कम हो जाएगा। राजस्व मंत्री ने कहा कि रैयतों की सुविधा के लिए भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया को पहले से सरल बनाया गया है। लोग अपने पास भूमि से संबंधित जो भी दस्तावेज उपलब्ध हैं, उसी के आधार पर आवेदन करें।

उन्होंने कहा कि आवेदन के लिए सभी दस्तावेजों की जरूरत नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि रैयत अपने पास भूमि से संबंधित जो भी दस्तावेज उपलब्ध हैं, उसी के आधार पर आवेदन करें और स्वलिखित वंशावली भी दें। उन्होंने कहा कि अब भूमि म्यूटेशन कराने के लिए कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है, अब सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

उन्होंने कहा कि म्यूटेशन के मामले में विभाग ने निर्णय लिया है कि 35 दिनों के अंदर भूस्वामी की जमीन का म्यूटेशन हो जाएगा, अगर किसी मामले में विवाद है तो 75 दिनों के अंदर उसका निष्पादन करना है। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के म्यूटेशन मामले में कागजात में कोई कमी है तो उसे सुनवाई के बाद भी रद्द करना है। अधिकारी को किसानों को बुलाना है, अगर कागजात की कमी है तो उन्हें कागजात उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में अभियान बसेरा 2 चल रहा है। जिसके तहत दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोगों के पास अगर जमीन नहीं है तो उन्हें जमीन उपलब्ध कराना है।

उन्होंने कहा कि सरकार एक नया प्रावधान भी लेकर आई है, जिन पंचायतों में जमीन नहीं है उन पंचायतों के लोगों को जमीन खरीदने के लिए मुख्यमंत्री वास नीति योजना के तहत एक लाख रुपए चेक के माध्यम से दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन चल रहे काम की मॉनिटरिंग भी की जाती है, बिहार में 10 ऐसे क्षेत्र हैं जहां सबसे ज्यादा म्यूटेशन के मामले रद्द किए गए हैं। वहां के अंचल अधिकारी से कारण पृच्छा की गई है। कारण पृच्छा से संतुष्ट नहीं होने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी।

एमवी एक्ट के तहत 194 ई-रिक्शा का हुआ चालान

कानपुर। शासन के आदेश के क्रम में व उच्चधिकारियों के निर्देशन में दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु शहर के प्रमुख चौराहों पर विशेष रुप से ई-रिक्शा वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर गलत दिशा में वाहन चलाने वालों, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, गलत नंबर प्लेट एवं बिना फिटनेस के सम्बन्ध में चेकिंग की गयी और यातायात नियमों का पालन न करने वाले ई-रिक्शा पर एमवी एक्ट के तहत सीज की कार्यवाही एवं 194 ई-रिक्शा का चालान किया गया।

वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन करने हेतु जागरुक किया गया। इस प्रकार की कार्रवाई के माध्यम से यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाता है। दुर्घटनाओं की रोकथाम में मदद मिलती है। वाहन चालकों को यह संदेश दिया जाता है कि यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

समस्तीपुर में जमीन विवाद में फायरिंग और पत्थरबाजी, पुलिस ने मौके से 2 खोखा बरामद किया

स्वतंत्र प्रभात

समस्तीपुर में जमीनी विवाद में गोलीबारी की घटना सामने आई। घटना जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के चांदचौर मध्य वार्ड संख्या-1 की जहां बुधवार की रात करीब 8:30 बजे दर्जन भर बदमाशों ने मंटुन चौरसिया के घर पर हमलाकर फायरिंग की। इस दौरान दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर ईट पत्थर भी फेंके। घटना की सूचना पर पहुंची उजियारपुर थाने की पुलिस ने मौके से दो खोखा भी बरामद किया है।

बताया गया है कि 2 कट्ठा जमीन को लेकर मंटुन चौरसिया और अमीर लाल चौरसिया के बीच पूर्व से विवाद चल रहा था। इस बीच बुधवार को दोपहर में मंटुन चौरसिया उक्त जमीन पर बाउंड्री वॉल करवा रहे थे। तब रामदुलार चौरसिया और उसके भाई शिवलाल चौरसिया ने आकर मारपीट की और फायरिंग शुरू कर दी। तब सुचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों दोनों पक्षों को अपना अपना कागज लेकर थाना पर बुलाया था। इसके बाद फिर देर रात करीब दर्जन भर लोग मंटुन चौरसिया के घर पर आए और बाउंड्री तोड़ने लगे। इस दौरान हमलावरों ने करीब 10 राउंड फायरिंग भी की। हालांकि इस गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दूसरे पक्ष की ओर से जब ईट-पत्थर चलाना शुरू हुआ तो हमलावर फरार हो गए। इस मामले में थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि दिनभर दोनों पक्षों के बीच कई बार झड़प हुई। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों से आवेदन मांगा था। लेकिन शाम को दोनों पक्ष फिर भीड़ गए। इस दौरान एक पक्ष की ओर कई राउंड फायरिंग भी की गई। सुचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से दो खोखा और कुछ अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद किया है। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषी पर कार्रवाई की जाएगी।

"समाजशास्त्रीय अध्ययन में परिवार एवं उनकी विशेषताएं" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

स्वतंत्र प्रभात

त्रिवेणीगंज (सुपौल)– अनूपलाल यादव महाविद्यालय, त्रिवेणीगंज के आइक्यूएसी (आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ) के तत्वावधान में समाजशास्त्र विषय से संबंधित "समाजशास्त्रीय अध्ययन में परिवार एवं उनकी विशेषताएं" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. हेमंत कुमार ने की, जबकि संचालन प्रो. अरुण कुमार द्वारा किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए विद्वानों एवं छात्र-छात्राओं ने परिवार की सामाजिक संरचना में भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि समाजशास्त्र में परिवार एक आधारभूत इकाई है, जो समाज की नींव और रीढ़ की तरह कार्य करता है। परिवार न केवल भावनात्मक संबंधों का केंद्र होता है, बल्कि सामाजिक नियमों, परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों के पालन की पहली पाठशाला भी होता है। उन्होंने यह भी बताया कि परिवार के सदस्य आपसी संबंधों के माध्यम से एक-दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं तथा उनके विचार, भावनाएं और व्यवहार पारस्परिक रूप से प्रभावित होते हैं।

कार्यशाला में समाजशास्त्र विभाग के प्राध्यापकगण प्रो. अनमोल कुमार, प्रो. छात्रधारी यादव, प्रो. अरविंद कुमार तथा महाविद्यालय के अन्य प्राध्यापकगण - प्रो. अरुण कुमार, डॉ. सुदीत नारायण यादव, प्रो. देवनारायण यादव, प्रो. शंभू यादव, प्रो. रामानंद यादव, प्रो. राजकुमार यादव, प्रो. जलधर यादव, प्रो. जयप्रकाश यादव सहित अनेक छात्र-छात्राएं - गगन कुमार, दिग्दर्शन, निशांत कुमार, रोशन कुमार, मुकेश कुमार, ललिता कुमारी, रेखा कुमारी, जालेश्वर भगत, रत्नेश कुमार, विपिन, बादल, कुणाल, राजकुमार, विकास, मानव, अभिषेक, सरोज, अरविंद, शाहजहां, ज्योति, मनीष, मुस्कान, अंजू, मंजू, तृप्ति, निक्की कुमारी तथा अन्य उपस्थित थे। कार्यशाला का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों की सक्रिय सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया।

श्रीमद् भागवत कथा के लिए निकाली गई कलश यात्रा

स्वतंत्र प्रभात

सिद्धार्थनगर। जिले के चिल्हिया क्षेत्र के बेलवा में गुरुवार को भव्य कलश यात्रा निकाल कर श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा वाचक उदय नारायण पाण्डेय के नेतृत्व मे गावं से यात्रा बानगंगा नदी से पवित्र जल भरने के लिए शुरू हुई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु शामिल रहीं। पवित्र जल कलश को भर कर गांव के प्राचीन काली मंदिर, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर व सभी देवी-देवताओं को आमंत्रित किया गया। यात्रा के बाद कलश कथा आयोजन स्थल पर धार्मिक विधि एवं मंत्रोच्चरण के साथ स्थापित किया गया। आरती के साथ शुरू किए गए श्रीमद् भागवत कथा के कथा वाचक उदय नारायण पाण्डेय ने उपस्थित श्रद्धालुओं को सर्वप्रथम इसकी महिमा से अवगत कराया।

कथा वाचक उदय नारायण पाण्डेय ने बताया कि विश्व में सभी कथाओं में ये श्रेष्ठ मानी गई है। जिस स्थान पर इस कथा का आयोजन होता है, वह स्थान तीर्थ स्थल कहलाता है। इसका सुनने एवं आयोजन कराने का सौभाग्य भी प्रभु प्रेमियां को ही मिलता है। ऐसे में अगर कोई दूसरा अन्य भी इसे गलती से भी श्रवण कर लेता है, तो भी वह कई पापों से मुक्ति पा लेता है। इसलिए सात दिन तक चलने वाली इस पवित्र कथा को श्रवण करके अपने जीवन को सुधारने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अगर कोई सात तक किसी व्यवस्तता के कारण नहीं सुन सकता है, तो वह दो तीन या चार दिन ही इसे सुनने के लिए अपना समय अवश्य निकालें। तब भी वो इसका फल प्राप्त करता है, क्योंकि ये कथा भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी है, जिसमें उनके अवतार से लेकर कंस वध का प्रसंग का उल्लेख होने के साथ साथ इसकी व्यक्ति के जीवन में महत्ता के बारे में भी बताया गया है। इसके सुनने के प्रभाव से मनुष्य बुराई त्याग कर धर्म के रास्ते पर चलने के साथ साथ मोक्ष को प्राप्त करता है। शास्त्री ने बताया कि इस कथा को सबसे पहले अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित ने सुना था, जिसके प्रभाव से उसके अंदर तक्षक नामक नाग के काटने से होने वाली मृत्यु का भय दूर हुआ और उसने मोक्ष को प्राप्त किया था। इस दौरान कथा आयोजक रोहित सिंह, कथा श्रोता पार्वती सिंह, रीता सिंह, मंजू सिंह, राधा सिंह, रीना सिंह, आरती सिंह, माही सिंह, निक्की सिंह, गुड्डी, दिवाली, काव्या, हर्षित, गगन, आदित्य, अक्षय उत्तरा आदि मौजूद रहे।

भृष्टाचार- संविदा की नौकरी के नाम सेवा प्रदाता संस्था द्वारा मोटी रकम की डिमांड

● संविदा की नौकरियों में जमकर चल रहा भ्रष्टाचार

योगी सरकार में मथुरा में बडा भ्रष्टाचार नौकरी लगवाने के लिए 80 हजार की मांग

स्वतंत्र प्रभात

मथुरा। जनपद में बेरोजगारी चरम पर है। लेकिन सरकारी कर्मचारी संविधान नौकरी लगवाने के नाम पर भी मोटा भ्रष्टचार कर रहे हैं इसमें सेवा योजन पोर्टल पर पंजीकृत सेवा प्रदाता संस्था अविका इंफ्राटेक कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड को सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से ई0ई0सी0ई0 एजुकेटर जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय के पदों को भरने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन नियुक्ति के लिए साक्षात्कार मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय पर आयोजित होने से पूर्व स्वयं प्रदाता संस्था के कर्मचारी ने अभ्यर्थियों को फ़ोन कर एक मोटी रकम 80 हजार ? की मांग की है वह आदमी डेविड अग्रवाल और अलोक पाण्डेय है जो कि ऑडियो रिकॉर्डिंग में अलोक पाण्डेय मोटी रकम की मांग करते कह रहा है कि आपकी नियुक्ति कर ली जाएगी। अभ्यर्थी कविता कुमारी ने मुख्य विकास अधिकारी से इस प्रकरण की शिकायत की है और आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत कर कहा गया है। कि ऐसी भ्रष्टाचारी संस्था पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए इसे ब्लैक लिस्ट किया जाए। जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का सपना साकार हो सके व कोई भी संस्था निकट भविष्य किसी युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके। मुख्य विकास अधिकारी ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है।

महंगी किताबों के लिए स्कूलों के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन

स्वतंत्र प्रभात

कानपुर। आज नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा एक समान शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था लागू किए जाने की मांग को कानपुर के पत्रकार व अधिवक्ता संगठित होकर एक साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में निजी स्कूलों की मनमानी रोकने, बढ़ती फीस, ड्रेस खर्च, कॉपी किताबो का खर्च के मानक निर्धारित किए जाने की मांग रखी गई, क्योंकि विद्यालयों की बढ़ती फीस व अन्य खर्च इतना अधिक होता जा रहा है कि अच्छे मेधावी बच्चों के अविभावको के लिए शिक्षा दिला पाना उनकी पहुंच से बाहर होता जा रहा है जो श्राप बनकर शिक्षा व्यवस्था के लिए संकट बन चुकी है इस पर रोक लगाना अति आवश्यक है।

नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट पंडित रविन्द्र शर्मा (पूर्व अध्यक्ष दि लॉयर्स एसोसिएशन कानपुर) एवं प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट अरविंद दीक्षित (पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष कानपुर बार एसोसिएशन) द्वारा प्रमुखता से इसकी सराहनीय पहल की गई और मांग की कि शिक्षा का एक मानक निर्धारित किया जाए जिससे अविभावक अपने बच्चों को सही से शिक्षा दिया सके। अत्यधिक फीस के चलते मेधावी बच्चे शिक्षा से वंचित न रह जाएं इसके लिए शिक्षा को व्यवसाय न बनाकर सेवाभाव के रूप में एक मानक निर्धारित करके इसे लागू किया जाए।

नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार को शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा सभी का जन्मसिद्धि अधिकार है लेकिन आज व्यवसाय बन चुकी शिक्षा व्यवस्था अविभावकों के लिए श्राप बनती जा रही है जिसे रोकना अति आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर मादक पदार्थों की अनैतिक बिक्री को लेकर पब्लिक स्टेटमेंट संपादक दिग्विजय सिंह की खबर प्रकाशन से नाराज होटल संचालक ने पत्रकार को दी जान से मारने की धमकी तो नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के दर्जनों पत्रकार व अधिवक्ता पुलिस कमिश्नर से मिले और धमकी देने वाले पर शख्त कार्यवाही करने की मांग की जिस पर कानपुर पुलिस कमिश्नर ने तत्काल उचित कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने का आश्वासन दिया।

महज चंद पल में ही खुशी हुई काफूर,बेचारे दूल्हे पर टूटा दुःख का पहाड़

● ठगों ने शादी के नाम पर 55 हजार रुपये भी ठगे

दिलवाली दुल्हनिया टॉयलेट के बहाने हुई फुर

स्वतंत्र प्रभात

त्रिवेणीगंज सुपौल। यू तो राजस्थान यूपी,पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों से अधेड़ दूल्हे कोसी के ग्रामीण इलाके के गरीब तबके के लड़कियों को आर्थिक प्रलोभन देकर साफ्ट टारगेट कर रहे हैं और दिल वाली दुलहनिया बना बयाह कर ले जाते है। लेकिन अब शादी के नाम पर ठगने वाले ठग भी अपनी बाजीगरी दिखाने में पीछे नहीं है ।ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।

ताजे मामला में राजस्थान के बीकानेर जिले से एक अधेड़ दूल्हे को शादी करवाने के लिए बुलाया गया और उनसे 55 हजार रुपए ठग लिए गए। वेसे ठगों ने शादी कराने का नायाब तरीका निकाला। शादी करने आये दूल्हे की बिधिवत शादी भी कराई गई,लेकिन ठगों ने गोपनीय ढंग से घूंघट में ढकी एक लड़की से बंद अंधेरे कमरे में नगर परिषद क्षेत्र के डपरखा में बिधिवत दूल्हे की शादी भी करवाकर कराई गई और फिर बिदाग़री की गई।लेकिन नई नवेली दुल्हन ने सिमराही में बाथरूम जाने के बहाने गाड़ी रूकवा कर रात के अंधेरे में फरार हो गई। लेकिन जब काफी खोजबीन के बाद भी दुल्हन नहीं मिली तो दूल्हे ,दलाल और दूल्हे के परिजन वापस लौट आये । घटना रविवार रात की बताई जा रही हैं।

बड़े पैमाने पर हो रही है शादी

अनुमंडल क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों एक गिरोह काफी सक्रिय हो गया है जो गरीबी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे भोले भाले अनपढ़ लोगों को उसकी बेटियों की शादी बड़े घराने में कराने का दिवा स्वप्न दिखाकर उसकी बेटियों को दूसरे राज्य खासकर उत्तर प्रदेश,राजस्थान,हरियाणा आदि राज्यों के अधेड़ पुरुषों के हाथों पैसे लेकर बेच देता है। इसी गिरोह के चंगुल में इस बार राजस्थान के बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के सूदसर गांव निवासी हीराराम जाघव उर्फ दूड़ाराम जाट के पुत्र 42 वर्षीय जगदीश जाघव उर्फ जगदीशराम जाट फंस गए और शादी के लिए राजस्थान से त्रिवेणीगंज आ गए। पीड़ित राजस्थानी दूल्हे ने आरोप लगाया कि त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के तितूवाहा वार्ड नंबर 10 निवासी संजय सरदार ने शादी कराने के लिए उन्हें बुलाया। संजय सरदार, जो वर्तमान में वार्ड सदस्य भी है, वह पहले बीकानेर में मजदूरी करता था, वहीं पर उसकी मुलाकात जगदीश और उसके दोस्तों से हुई थी।

बकौल दूल्हा जगदीश राम, संजय ने उसे सुंदर लड़की से शादी कराने का लालच दिया और 55 हजार रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद उसे डपरखा ले जाकर एक बंद कमरे में घूंघट में छिपी लड़की के साथ बिना किसी रीति-रिवाज के सिंदूर भरवा कर शादी कराई। शादी होने के बाद जब वे लड़की को लेकर वापस राजस्थान लौट रहे थे, तभी सिमराही में रात के समय दुल्हन टॉयलेट के बहाने गाड़ी से उतरकर भाग गई।

काफी तलाश के बाद भी जब लड़की नहीं मिली, तो दूल्हा, उसके परिजन और दलाल वापस त्रिवेणीगंज लौट आए और जब राजस्थानी दूल्हे और उनके परिजनों को ठगी का एहसास हुआ तो सोमवार को थाना पहुंचकर एक लिखित शिकायत की। जगदीश राम का कहना है कि ठगी का एहसास होने पर जब उन्होंने दलाल से बात की तो वह धमकी देने लगा। इस पूरे मामले में एक महिला भी संलिप्तता है। पीड़ित दूल्हे के परिजनों का आरोप है कि संजय सरदार अब तक कई शादियाँ इस तरह रुपए लेकर करा चुका है। अब राजस्थानी दूल्हे और उसके परिजनों ने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की गुहार लगाई है।

फीस में मृद्धि ड्रेस किताबों में कमीशन, अभिभावकों पर दोहरी मार

● निजी स्कूल संचालाकों की मनमानी के आगे अभिभावक असहाय

स्वतंत्र प्रभात

मथुरा। निजी स्कूल शिक्षा के लुभावने वायदों से हकीकत जुदा है। फीस में वृद्धि का रोना अभिभावक कलेक्टर तक रो कर आये हैं। स्कूलों का ड्रेस और किताबों में कमीशन अलग से। स्कूलों में नवीन सत्र के प्रारंभ होते ही अभिभावकों की परेशानी शुरू हो गई है। जिसमे अधिकतर प्राइवेट बिद्यालय संचालको द्वारा छात्रों की किताबें मनमानी कीमतों पर चुनिंदा और तयशुदा दुकानों पर बिक्री कराई जा रही हैं। जैसे राया क्षेत्र के अधिकतर विद्यालयों की किताबें कस्बे के बलदेव रॉड स्थित .एक पुस्तक भंडार पर मिलेंगी यह अभिभवकों को पहले ही बता दिया जाता है। दूसरे कस्बा और महानगर में भी यही स्थिति है। जो बिद्यालय संचालको को मोटा कमीशन देकर अभिभावकों की जेबो पर डांका डाल रहा है। जिससे अभिभावक खासे परेशान है। पाल्यो को पढ़ाने एवं विद्यालय संचालको के दबाब के चलते अभिभावकों को निज विक्रेता से ही किताबे लेनी पड़ रही है। महंगी किताबें, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म स्कूलों से खरीदना अभिभावकों की मजबूरी है। चुनिंदा दुमानों पर प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें लगवाई गई है, जिनकी कीमत आसमान छू रही है। कॉपी किताब भी विद्यालय या विद्यालय के निज विक्रेता से खरीदने का विद्यालय संचालक अभिभावकों पर दबाब बनाते है। वही किताबें अन्य पब्लिकशेन से खरीदने पर किताबो के दामो में भारी अंतर मिलता है। किताबो को किसी अन्य पब्लिकेशन से खरीदा जाएगा तो बिद्यालय में मान्य नही होंगी। कॉपी किताब का सेट इतना महंगा है कि उसे खरीदने में अभिभावकों के पसीने छूट रहे है। कई निजी स्कूलों में तो पहली से आठवीं कक्षा की किताबों का सेट छह से 10 हजार रुपये में दिये जा रहे हैं।

प्रशासन और शिक्षा विभाग इस लूट पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब इसे इनकी मिलीभगत कहें या अनदेखी जिससे विद्यालय संचालक लूट खसूट करने में लगे है। इन दिनों सभी पुस्तक विक्रेताओं के यहां अभिभावकों की लंबी लंबी लाइनें लग हैं। परिजन बच्चों की किताब खरीदने चुनिंदा दुकानों पर पहुंच रहे हैं। स्कूलों द्वारा तय निजी प्रकाशकों की किताबें एनसीईआरटी की किताबों से पांच गुना तक अधिक महंगी हैं। अधिकांश निजी स्कूल संचालक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की किताबें मंगवाने में रुचि नहीं दिखाते। निजी विद्यालयों में 80 फीसदी निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें पढ़ाई जाती हैं। इन किताबों की कीमत एनसीईआरटी से कई गुणा अधिक होती हैं। कई किताबों में तो प्रिंट रेट के ऊपर अलग से प्रिंट स्लिप चिपकाकर प्रकाशित मूल्य से कहीं अधिक वसूली की जा रही है। निजी स्कूलों में कमीशन के चक्कर में हर साल किताबें बदलने के साथ अलग अलग प्रकाशकों की

महंगी किताबें लगाई जाती हैं। एनसीईआरटी की 256 पन्नों की एक किताब 65 रुपये की है तो वहीं निजी प्रकाशक की 167 पन्नों की किताब 305 रुपये में मिल रही है। कई किताबों की कीमत 500 से 600 रुपये तक है। जिस प्रकार बुक सेलर बिना टेक्स पेढ बिल देकर करोड़ो रूपये की किताबो से लाखो रुपये की जीएसटी की चोरी कर रहे हैं।

वीवीआईपी कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर प्रमुख सचिव एवं डीजीपी का निरीक्षण कानपुर दौरा

स्वतंत्र प्रभात

कानपुर। आगामी वीवीआईपी कार्यक्रम को लेकर आज दिनांक 17.04.2025 को उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह एवं डीजीपी उ0प्र0 प्रशान्त कुमार महोदय द्वारा कानपुर नगर का भ्रमण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा रूट व्यवस्था, मेट्रो स्टेशन, हैलीपैड, जनसभा स्थल एवं पार्किंग स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए गए, जिससे कि कार्यक्रम के दौरान सभी व्यवस्थाएँ सुचारु रूप से संचालित की जा सकें।

निरीक्षण के उपरांत चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर (CSA) विश्वविद्यालय परिसर में एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें तैयारियों की समीक्षा की गई। गोष्ठी में एडीजी जोन कानपुर आलोक सिंह, पुलिस आयुक्त अखिल कुमार, मंडलायुक्त कानपुर के. विजेयेंद्र पांडियन, आईजी रेंज कानपुर जोगेंद्र कुमार, जिलाधिकारी कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह, अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) हरीश चंदर सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे। प्रशासन द्वारा सुरक्षा, यातायात और जनता की सुविधा को लेकर सभी तैयारियाँ सुनिश्चित की जा रही हैं।